वर्ष 13 • अंक 40 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 7 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

थोक बाजार में 3 रुपये किलो तक लुढ़के प्याज के दाम

एन चंद्रशेखरन पृष्ठ 2

टाटा जुटाएगी 7,000 करोड़ रुपये

एक नज़र

महावीर जयंती पर बंद रहे शेयर और जिंस बाजार

महावीर जयंती पर सोमवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार बंद रहे। इसके साथ ही सराफा और अन्य प्रमुख थोक बाजारों में भी अवकाश रहा।

कोरोना के चलते सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट

देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में मार्च में गिरावट देखी गई। एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोनावायरस संकट के चलते मांग में आई कमी की वजह से सेवा क्षेत्र में यह संकुचन देखा गया। कंपनियों के खरीद प्रबंधकों के बीच किए जाने वाले मासिक सर्वेक्षण पीएमआई सेवा की सोमवार को जारी मार्च की रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए। मार्च में पीएमआई सेवा सूचकांक 49.3 अंक पर रहा, जो फरवरी में 85 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचकर 57.5 अंक था। सर्वेक्षण के लिए आंकड़े 12 से 27 मार्च के बीच जुटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस वजह से सेवा क्षेत्र की मांग में व्यापक कमी देखी गई है।

कोरोना संक्रमण की वजह से मुंबई के दो अस्पताल सील

लोगों की जान बचाने वाले चिकित्साकर्मियों की भी कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़ने लगे हैं। मुंबई के बड़े अस्पताल वॉकहार्ट में 26 नर्सों और तीन डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल में काम करने वाले 270 से ज्यादा कर्मचारियों और डॉक्टरों की जांच कराई जा रही है। मुंबई के एक अन्य अस्पताल जसलोक हॉस्पिटल को भी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यहां की छह नर्सों समेत 19 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी तरह चंडीगढ़ प्रतिष्ठित अस्पताल पीजीआईएमईआर के 30 चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को संक्रमित रोगी के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन में भेज दिया गया है।

कोरोना में मृत्यु दावे स्वीकार करेंगी बीमा कंपनियां

जीवन बीमा परिषद ने सोमवार को कहा कि सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते हुई मौत की स्थिति में दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं। परिषद ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड-19 से संबंधित किसी भी मृत्यु दावे के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिषद ने कहा कि कोविड-19 से मौत के दावों के मामले में फोर्स मेजर का प्रावधान लागू नहीं होगा। फोर्स मेजर का अर्थ है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति जब समझौते का पालन बाध्यकारी नहीं होता।

कोविड-19 से जीडीपी वृद्धि पर प्रतिकूल असर

कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है और असर गंभीर होने से आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भी हो सकती है। यूबीएस में भारत की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नरमी लॉकडाउन की अवधि और नीति निर्माताओं द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा। अगर स्थिति मई तक सामान्य होती है तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 में 4 फीसदी रह सकती है। हालांकि सितंबर तक मामला खिंचने पर 2020-21 में विकास दर ऋणात्मक 0.2 फीसदी रह सकती है।

सांसदों के वेतन में कटौती

कोरोना से निपटने के लिए सांसद निधि भी दो साल के लिए रुकी रहेगी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अप्रैल

कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के साथ ही सभी सांसदों ने भी वेतन का एक हिस्सा देने पर सहमति जताई है। जन प्रतिनिधि वित्त वर्ष 2020-21 में 30 फीसदी कम वेतन लेंगे और यह राशि देश की संचयी निधि में जमा होगी।

इसके अलावा सांसद विकास निधि भी दो साल यानी 2020-21 और 2021-22 तक निलंबित रहेगी। करीब 7,900 करोड़ रुपये की यह राशि भी घातक कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए संचयी निधि में हस्तांतरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने सांसदों और मंत्रियों के वेतन में कटौती से संबंधित अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसकी जानकारी दी। इस अध्यादेश के जरिये सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े 1954 के कानून में संशोधन किया जाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए लागू होगा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपालों ने भी अपने वेतन में 30 फीसदी कटौती की पेशकश की है। जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए किसी अध्यादेश की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती की पेशकश की है। उन्होंने यह तो बताया कि सांसद निधि से कितनी राशि मिलेगी लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया कि वेतन कटौती से सरकारी खजाने में कितनी राशि आएगी। साथ ही जावड़ेकर ने यह भी नहीं बताया कि कटौती मूल वेतन में की जाएगी या कुल वेतन में। अलबत्ता, अगर मूल वेतन में कटौती की जाती है तो यह योगदान 32 करोड़ रुपये होगा। अगर कुल वेतन में कटौती की जाती है तो यह राशि कहीं अधिक होगी। जावडेकर ने कहा कि इसमें पैसों से ज्यादा नीयत की अहमियत है क्योंकि इससे सही संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे सही संदेश जाएगा। परोपकार की शुरुआत घर से होती है।'

- एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन लेंगे सांसद
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी स्वेच्छा से कम वेतन लेंगे
- इससे बची राशि देश की संचयी निधि में जमा होगी

जहां कम जोखिम, वहां लॉकडाउन हटाने के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों को उन इलाकों में धीरे-धीरे विभिन्न विभाग खोलने की योजना तैयार करने के लिए कहा है, जहां कोरोनावायरस के मामले कम हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले असर को कम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा। पृष्ठ 8

मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की। उन्होंने कहा कि इस संकट से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा और इससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री ने ऐप आधारित कैब की तर्ज पर किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए ट्रक एग्रीगेटर जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशन के इस्मेताल की संभावनाएं तलाशने की भी आह्वान किया। अधिकांश सांसदों ने संकट की इस घड़ी में वेतन में कटौती का स्वागत किया लेकिन सांसद निधि पर दो साल तक रोक लगाने के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा के उनकी पार्टी सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले का स्वागत करती है लेकिन सांसद निधि रोके जाने से सांसद की भूमिका कमजोर होगी और कामकाज प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, 'सांसद निधि का मकसद संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए है।'

भाजपा के राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा ने कहा, 'जो भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है वह देशद्रोही है। सांसद निधि किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह देश के लोगों का पैसा है। अगर प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए खर्च करने का फैसला किया है तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो इसमें कमीशन खाते हैं।'

बजाज फाइनैंस ने साढ़े तीन लाख ग्राहक गंवाए

बजाज फाइनैंस का लेखाजोखा

	नए ग्राहक	नया कर्ज	एयूएम	वृद्धि*
2019 की चौथी तिमाही	19.2	58.0	1,15,888	–
2020 की पहली तिमाही	24.6	72.7	1,28,898	11.2
2020 की दूसरी तिमाही	19.2	64.7	1,35,533	5.1
2020 की तीसरी तिमाही	24.6	77.6	1,45,092	7.1
2020 की चौथी तिमाही	19.0	60.0	1,47,600	1.7

नोट : ग्राहक और कर्ज के आंकड़े लाख में, एयूएम करोड़ रुपये में।
*तिमाही आधार पर वृद्धि फीसदी में — स्रोत : कंपनी प्रजेंटेशन

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 6 अप्रैल

बजाज फाइनैंस के प्रबंध निदेशक राजीव जैन के नेतृत्व वाली प्रबंधन टीम ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में सोमवार को बताया कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 10 दिन के दौरान, कंपनी को लगभग 3,50,000 ग्राहक गंवाने पड़े हैं, जिससे उसकी प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) पर 4,750 करोड़ रुपये (31 मार्च 020 तक कुल एयूएम का 3.22 प्रतिशत) तक का प्रभाव पड़ा।

जैन का कहना है, 'हम अनिश्चितता के दौर में हैं। हम 15 अप्रैल से 30 जून के बीच गंभीर अनिश्चितता के संकट में आ जाएंगे।' अप्रत्याशित लॉकडाउन की वजह से देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता वित्त कंपनी प्रभावित हुई है।

बेहद छोटी अवधि की अप्रैल-जून 2020 तिमाही (लॉकडाउन की वजह से 60 दिन की तिमाही का अनुमान) में कंपनी के प्रदर्शन मानकों पर बड़ा दबाव देखा जा सकता है।

कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है और यदि लॉकडाउन को 14 अप्रैल को समाप्त कर दिया जाता है तो उसका कारोबार सितंबर 2020 तक ही सामान्य स्थिति में लौट पाएगा। ज्यादा खराब हालात में, व्यवसाय को पटरी पर लौटने में मार्च 2021 की तिमाही तक का वक्त लग सकता है।

- लॉकडाउन आगे बढ़ने से परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर पड़ेगा असर
- ऋण लागत में 40-50 प्रतिशत तक का हो सकता है इजाफा
- नए ऋणों में तिमाही आधार पर लगभग 22 प्रतिशत तक की गिरावट

बजाज फाइनैंस ने चौथी तिमाही के लिए कुछ प्रमुख प्रदर्शन आंकड़े जारी किए हैं। नई ग्राहक वृद्धि और मार्च तिमाही के लिए नए ऋण वितरण की रफ्तार वित्त वर्ष 2015 के बाद से सबसे कमजोर रही है और वित्त वर्ष 2017 की नोटबंदी-प्रभावित तिमाहियों की तुलना में भी दबाव ज्यादा दिख रहा है।

नए ग्राहक जोड़ने की दर 22.8 प्रतिशत की कमी के साथ 19 लाख रही जो दिसंबर 2019 की तिमाही में 24.6 लाख थी। यह एक साल पहले की तिमाही के 19.2 लाख ग्राहकों के मुकाबले भी कम है। इसी तरह, नए ऋण तिमाही आधार पर 22.7 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ 60 लाख के आंकड़े पर रह गए, हालांकि सालाना आधार पर इस आंकड़े में महज 3.5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई।

विश्लेषकों का मानना है कि बजाज फाइनैंस के शेयर में मंगलवार के कारोबार में कमजोरी देखी जा सकती है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने कहा, 'शेयर पर कमजोर वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता का असर दिखेगा और इससे निवेशक इसके महंगे मूल्यांकन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।'

भले ही प्रबंधन ने अपना सतर्क आशावादी रुख अपनाए रखा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय का नुकसान ऋणदाता के लिए काफी ज्यादा है।

व्यावसायिक प्रभाव से मुकाबले के लिए कंपनी अपनी परिचालन लागत को नियंत्रित बनाए रखेगी। कंपनी ने नई नियुक्तियों, यात्रा और शाखा विस्तार जैसी योजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे उसे लागत में 7-8 प्रतिशत की बचत में मदद मिल सकती है। दबाव लंबे समय तक बने रहने की स्थिति में कंपनी ज्यादा लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। परिचालन में सुधार काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आर्थिक गतिविधियां देश में कब पुन: शुरू होती हैं।

जल्द हटेगी दवा निर्यात से पाबंदी!

सोहिनी दास
मुंबई, 6 अप्रैल

अमेरिका जैसे देशों से आ रहे दबाव और चीन से आपूर्ति धीरे-धीरे जोर पकड़ने के बीच भारत कुछ खास रसायनों (एपीआई) और दवाओं के निर्यात पर लगी पाबंदी हटा सकता है। इनमें कोरानावायरस के इलाज में संभवत: प्रभावी माने जाने वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन (एचसीएक्यू) भी शामिल है।

दो सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि भारत दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति शुरू होने से हालात उतने नाजुक नहीं रह गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'कोविड-19 संक्रमण के बाद देश में पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।

खासकर पैरासिटामोल जैसी दवाओं का निर्यात रोक दिया गया था। इन दवाओं में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायनों का आयात मुख्य रूप से चीन के हुबेई प्रांत से होता था। अब स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, इसलिए सरकार दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है।'

घरेलू बाजार में मुख्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और इनसे बनने वाली दवाओं का निर्यात रोक दिया था। जिन दवाओं का निर्यात रोका गया था, उनमें पैरासिटामोल, विटामिन, एंटी-वायरल, हार्मोन और सामान्य एंटीबायोटिक्स (टिनिडाजोल, मेट्रोनिंडजोल) जैसी दवाएं शामिल थीं। इन दवाओं के निर्यात से पहले निर्यातकों को सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। हालांकि निर्यात से जुड़ी प्रक्रिया जटिल होने के कारण मार्च में षायद ही इनमें किसी दवा का निर्यात हुआ होगा।

भारत ने एचसीक्यू का निर्यात भी रोक दिया था। कोविड-19 के इलाज में कारगर होने की खूबी होने का कारण इस दवा की मांग अचानक बढ़ गई थी।

मार्च के अंतिम सप्ताह में सरकार ने मानवीय आधार पर स्थिति की गंभीरता समझते हुए इसकी सीमित मात्रा में निर्यात की इजाजत दी थी। हालांकि 4 अप्रैल को भारत ने इस दवा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

करीब दो दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को एचसीक्यू की आपूर्ति करने का आग्रह किया था।

दवा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत एचसीक्यू सहित 13 रसायनों और उनसे बनने वाली दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा सकता है।

- चीन से दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की आपूर्ति में हो रहा सुधार
- अमेरिका जैसे देशों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की
- 13 रसायनों एवं दवाओं से हट सकती है पाबंदी

कुछ इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले

देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 111 पहुंच गई, वहीं 4,281 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। अब तक 318 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 704 नए मामले आए और 28 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत कोरोना संक्रमण के दूसरे और तीसरे चरण के बीच में है और कुछ खास इलाकों में ज्यादा मामले देखे गए हैं। एम्स के निदेशक और कोविड-19 के लिए गठित कार्यबल के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश के कुछ इलाकों में स्थानीय समुदायों में इसका प्रसार हुआ है। *एजेंसी*

भारत में लोकप्रिय हो रहे जूम पर चीन से खतरा!

नेहा अलावधी और पीरजादा अबरार
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 6 अप्रैल

लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के बारे में खबरें आ रही है कि इसमें हैकिंग का खतरा है और हाल में एक जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी कुछ गोपनीय जानकारी चीन भेजती है। लेकिन भारत अभी इससे बेखबर है और इस ऐप की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

शुक्रवार को कनाडा की एक स्वतंत्र शोध संस्था सिटिजन लैब्स ने खुलासा किया कि जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के वितरण के वास्ते चीन के सर्वरों का इस्तेमाल किया गया। सिटिजन लैब्स के शोधकर्ताओं ने कहा, 'हमें संदेह है कि की चीन के सर्वरों के जरिये जानकारी वितरित की जा रही हैं। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के ग्राहकों को सेवा देने वाली एक कंपनी कभी-कभी चीन के सर्वर से एनक्रिप्शन का वितरण करती है। यह चिंताजनक है क्योंकि जूम को चीन के अधिकारियों के समक्ष इनका खुलासा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि एंड टु एंड एनक्रिप्शन का कंपनी का दावा भ्रामक है।'

हाल के दिनों में जूम बेहद लोकप्रिय बनकर उभरा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण अधिकांश देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और लोग घरों से काम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह गूगल प्ले से डाउनलोड के मामले में इसने व्हाट्सऐप और टिकटॉक को भी पीछे छोड़ दिया था।

कनाडा की संस्था के खुलासे के जवाब में जूम के मुख्य कार्याधिकारी एरिक युआन ने ब्लॉगपोस्ट किया कि ऐप में अचानक यूजर की बाढ़ आ गई है और यही वजह है कि कंपनी जियो फेंसिंग की अपनी व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा, 'फरवरी में जूम ने चीन में भारी मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का तेजी से विस्तार किया। जल्दबाजी में गलती से हमने चीन के दो डेटा सेंटरों को बैकअप ब्रिज की सूची में जोड़ दिया जो चीन के बाहर के लोगों से जुड़े थे।' उन्होंने साथ ही कहा कि इस गलती का जूम फॉर गवर्नमेंट क्लाउड पर कोई असर नहीं हुआ। यह सरकारी ग्राहकों के लिए कंपनी की अलग क्लाउड सेवा है। कई भारतीय कंपनियां और यहां तक की सरकारी बैठकें भी जूम पर होती हैं। इस तरह के खुलासों और लिंक्डइन तथा फेसबुक के साथ यूजर डेटा साझा करने से निजता से जुड़ी चिंता और जूमबॉम्बिंग के कारण कैलिफोर्निया के सैन होजे की इस कंपनी को टेस्ला और न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफएजुकेशन जैसे ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा है। ऐसा देखनें में आया है कि जूमबॉम्बिंग में लोग बिना बुलाए जूम की बैठकों में घुस जाते हैं और हेट स्पीच तथा अश्लील तस्वीरें साझा करते हैं। हालांकि भारत में जूम लोकप्रिय हो रहा है और इन खुलासों का उसके कारोबार पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियां और सरकारें लगातार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में 30 मार्च को एक परामर्श जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अपने डेटा के संरक्षण के लिए यूजर को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

जूम का सुरक्षित उपयोग कैसे करें

- जूम सॉफ्टवेयर को हर बार अपडेट करें
- मजबूत और मुश्किल पासवर्ड बनाएं
- ज्यादा सुरक्षित मीटिंग के लिए वेटिंग रूम फीचर को सक्रिय करें
- 'ज्वॉइन बीफोर होस्ट' फीचर को निष्क्रिय करें
- संभव हो तो फाइल ट्रांसफर को निष्क्रिय करें
- सभी लोगों के शामिल होने के बाद मीटिंग को लॉक कर दें

व्यापार गोष्ठी

कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरु हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या दवा निर्यात से पाबंदी हटाना उचित होगा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाना सही कदम होगा?	हां	33.33%
	नहीं	66.67%

संक्षेप में

इन्फोसिस के सीओओ राव बने नैसकॉम के चेयरमैन

सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग की निकाय नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव को साल 2020-21 के लिए चेयरमैन नामित किया। एक्सेंचर इंडिया की चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबंधकीय निदेशक रेखा मेनन को वाइस चेयरपर्सन नामित किया। पिछले साल राव वाइस चेयरमैन थे और उन्होंने डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज के केशव मुरुगेश की जगह ली है। *बीएस*

मार्च तिमाही में सुधरेगी मोबाइल ऑपरेटरों की स्थिति

दूरसंचार कंपनियों की आय और कर पूर्व लाभ की स्थिति जनवरी-मार्च तिमाही में बेहतर होने की उमीद है। इसकी एक बड़ी वजह दिसंबर में कंपनियों का मोबाइल प्लान थोड़ा महंगा करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की वित्तीय सेहत पर इसका पूरा अनुकूल प्रभाव चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के अंत तक दिखेगा। ऐक्सिस कैपिटल ने दूरसंचार उद्योग को लेकर अपने आकलन में यह बात कही है। *भाषा*

रेटिंग वाली फर्में जुटाएंगी रकम

आरबीआई से रकम जारी होने के बाद शीर्ष रेटिंग वाली कंपनियां इस दौड़ में शामिल

देव चटर्जी और जयदीप घोष
मुंबई, 6 अप्रैल

- शीर्ष रेटिंग वाली कई कंपनियां 1 अप्रैल से बैंकों से जुटा रहीं ऋण
- कंपनियां पुराने ऋण को चुकाकर घटा रहीं वित्तीय लागत
- एलऐंडटी, एचडीएफसी, आरआईएल भी ऋण लेने की कतार में

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से व्यवस्था में नकदी झोंकने के लिए विशेष खिड़की खोले जाने के बाद टाटा संस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलऐंडटी और एचडीएफसी उन कंपनियों में शामिल हैं जो बैंकों से कम लागत वाला फंड जुटा रही हैं। यह कहना है बैंकरों का।

बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, टाटा संस करीब 7,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है और उसकी योजना उच्च लागत वाले पुराने कर्ज के निस्तारण में इस फंड का इस्तेमाल करने की है। सूत्र ने कहा, 'यह अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के लिए रकम जुटाने का एक अच्छा अवसर है। एचडीएफसी की योजना करीब 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की है। आरबीआई ने 27 मार्च को रीपो दर में 75 आधार अंकों की कमी करने के अलावा बैंकों को अतिरिक्त रकम भी जारी की है। आरबीआई ने कहा था कि 27 मार्च 2020 तक के निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में नकदी प्रवाह सुनिश्चित की गई है। बैंकों ने कंपनियों को ऋण देने के लिए आरबीआई से दो किस्तों में 50,000 करोड़ रुपये पहले ही जुटा लिए थे। सूत्रों ने कहा कि यही कारण है कि पिछले सप्ताह कई शीर्ष कंपनियों ने बैंकों से रकम जुटाई थी। उन्होंने कहा, 'बैंक फिलहाल रकम बहा रहे हैं और वे शीर्ष रेटिंग वाली कंपनियों को उधारी देना चाहते हैं।'

इस विशेष खिड़की के अलावा आरबीआई ने 28 मार्च 2020 को बैंकों के नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में भी 100 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे शुद्ध मांग का 3 फीसदी कर दिया था। साथ ही 28 मार्च 2020 से एक साल की अवधि के लिए देनदारियों के लिए समय को पखवाड़ा कर दिया था। सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से करीब 1,37,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी प्रवाह जारी होगा। बैंकरों ने कहा कि अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली भारतीय कंपनियां अपने पूंजीगत खर्च अथवा नई परियोजना पर खर्च के लिए रकम जुटा सकती हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज दूरसंचार कारोबार में निवेश कर रही है (मुख्य रूप से पूंजीगत निवेश), वहीं टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी वित्त वर्ष 2020 में वित्तीय सेवा एवं विमानन जैसे अपने नए कारोबार में लगातार निवेश करती रही है। इसी क्रम में टाटा संस ने टाटा कैपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज और अपनी दो विमानन कंपनियों में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एक सूत्र ने कहा कि विमानन क्षेत्र लॉकडाउन के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और ऐसे में टाटा संस को टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड और एयर एशिया इंडिया लिमिटेड में निवेश करना पड़ेगा। टाटा संस को मार्च 2020 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 3,333 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी करनी थी। कंपनी पर शुद्ध ऋण बोझ करीब 30,000 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष में टाटा संस ने टाटा रियल्टी ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में अतिरिक्त 580 करोड़ रुपये निवेश किया ताकि कंपनी कर्ज घटाने और नई परियोजना में निवेश में सक्षम हो।

खुदरा निवेश पर 3 लाख करोड़ रु. की चोट

जश कृपलानी
मुंबई, 6 अप्रैल

बाजार में हुई तेज बिकवाली से खुदरा निवेशकों की तरफ से सीधे किए गए इक्विटी निवेश पर भारी असर पड़ा है और मौजूदा कैलेंडर वर्ष में उनके निवेश पर करीब 3 लाख करोड़ रुपये की चोट पड़ी है कैपिटालाइन के आंकड़ों से पता चलता है कि 31 दिसंबर 2019 के आखिर में खुदरा निवेशकों (वैयक्तिक क्षमता से 2 लाख रुपये तक निवेश करने वाले) के पास एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 3,000 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों में 9.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश था। 3 अप्रैल 2020 को इस निवेश की कीमत घटकर 6.87 लाख करोड़ रुपये रह गई है। इस विश्लेषण में सक्रियता से ट्रेड होने वाले शेयरों को ही शामिल किया गया।

विशेषज्ञों ने कहा, जब बाजार एतिहासिक ऊंचाई पर था तो इन निवेशकों ने बड़ी पोजिशन खड़ी की थी

इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी के संस्थापक व प्रबंध निदेशक जी चोकालिगम ने कहा, खुदरा निवेशकों के निवेश पर बड़ी चोट पड़ी है, जो विभिन्न क्षेत्रों व शेयरों में निवेशित थे। ऐसे निवेशकों में से ज्यादातर की प्रवृत्ति उस समय बड़ी पोजिशन बनाने की थी जब मूल्यांकन महंगे थे और मंदी के ऐसे बाजारों में उनके पोर्टफोलियो को भारी झटका लगा है। बाजार के प्रतिभागियों के मुताबिक, खुदरा निवेशकों ने उस समय बाजार में पोजिशन में इजाफा किया जब बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर था। लेकिन मुख्य सूचकांकों मसलन सेंसेक्स व निफ्टी जनवरी के अपने उच्चस्तर से 34 फीसदी से ज्यादा टूटे हैं।

ब्लूचिप कंपनियों मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज (-20,751 करोड़ रुपये), एचडीएफसी बैंक (-18,687 करोड़ रुपये), लार्सन ऐंड टुब्रो (-14,266 करोड़ रुपये), एचडीएफसी (-10,621 करोड़ रुपये) और बजाज फाइनैंस (-8,235 करोड़ रुपये) में भारी मार्क टु मार्केट नुकसान के अलावा खुदरा निवेशक चवन्नी व कम कीमत वाले शेयरों में भी बुरे फंसे।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि कम कीमत वाले शेयरों ने खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया क्योंकि उन्हें ऐसे शेयरों में गिरावट और रिकवरी के समय तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद की थी। एक ब्रोकिंग हाउस के विश्लेषक ने कहा, खुदरा निवेशक ऐसे शेयरों पर नजर रखते हैं ताकि वे कुछ ही निवेश लागत पर भारी मात्रा में शेयर उठा सकें।

10 रुपये वाला शेयर 2 लाख के निवेश पर 20,000 शेयर मिलेगा, वहीं 100 रुपये वाला शेयर 2,000 ही मिल पाएगा।

अभी 5 रुपये पर कारोबार करने वाले साउथ इंडियन बैंक का शेयरों में खुदरा निवेश की वैल्यू 330 करोड़ रुपये सिकुड़ी है। वोडाफोन आइडिया में खुदरा निवेशकों की निवेश वैल्यू 170 करोड़ रुपये घटी है जबकि रिलायंस पावर में 124 करोड़ रुपये कम हुई है।

वाहन डीलरों को भारी नुकसान का डर

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 6 अप्रैल

वाहन डीलरों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होने का डर है क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वे अपने बीएस4 वाहनों के स्टॉक के एक बड़े हिस्से को नहीं बेच पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च को दी गई 10 दिनों की मोहलत से उन्हें इस स्थिति से निपटने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि वाहनों के पंजीकरण में इस्तेमाल होने वाले वाहन पोर्टल भी बंद है और यदि इसे नहीं खोला गया तो डीलरों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में वे अपने बीएस4 वाहनों के स्टॉक को नहीं खपा पाएंगे। मौजूदा परिस्थिति में डीलर केवल 24 अप्रैल तक बीएस4 वाहनों की बिक्री कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह रियायत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए नहीं होगी जिससे इस क्षेत्र के डीलर काफी चिंतित हैं। केयर रेटिंग्स ने कहा है कि वाहन उद्योग समय-सीमा में 30 जून तक यानी तीन महीने के विस्तार की मांग कर रहा है और 10 दिनों के विस्तार से उद्योग को कोई खास मदद नहीं मिलेगी। लॉकडाउन की अवधि बीतने के बाद ग्राहकों में खरीद धारणा कमजोर रहने के आसार हैं। लॉकडाउन के बाद ग्राहक खर्च करने में काफी सावधानी बरतेंगे, विशेष तौर पर लक्जरी अथवा महंगी वस्तुओं की खरीदारी के मामले में।

कोविड-19 के प्रभाव पर केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'यदि इस वैश्विक महामारी को नियंत्रित कर लिया जाता है तो भी वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के दौरान ग्राहक धारणा अनुकूल न रहने और मांग में सुस्ती बरकरार रहने के आसार हैं। इसे बाजार में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य से बल मिलेगा।'

स्विगी ने जुटाए अतिरिक्त 4.3 करोड़ डॉलर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 6 अप्रैल

ऑनलाइन फूड डिलिवरी फर्म स्विगी ने मौजूदा सीरीज की फंडिंग में 4.3 करोड़ डॉलर अतिरिक्त जुटाए हैं, जिसमें मौजूदा निवेशकों टेनसेंट के अलावा नए निवेशकों मसलन आर्क इम्पैक्ट, कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, सैमसंग वेंचर्स और मिरे ऐसेट कंपनी शामिल है। इस रकम के अलावा कंपनी ने इस दौर में 15.6 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस कवायद के बाद स्विगी का मूल्यांकन मामूली बढ़कर 3.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, जो फरवरी के मूल्यांकन 3.5 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा है और तब कंपनी ने मौजूदा निवेशकों प्रोसस एनवी और एम डायपनिंग और वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी से 11.3 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

स्विगी के सीएफओ राहुल बोथरा ने कहा, विभिन्न वर्षों में स्विगी ने स्थायी फूड डिलिवरी कारोबार बनाया है, साथ ही विभिन्न ग्राहकों की समस्याओं का समाधान भी किया है। हमारा ध्यान अपने विजन को लागू करने पर है और हम लाभ के लिए स्थायी मार्ग बना रहे हैं।

म्युचुअल फंड के लिए बदला कट-ऑफ समय

जश कृपलानी
मुंबई, 6 अप्रैल

बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंडों को इक्विटी व डेट योजनाओं के लिए कट-ऑफ समय 3 बजे से घटाकर एक बजे करने और लिक्विड व ओवरनाइट योजनाओं के लिए 1.30 बजे से 12.30 बजे करने की अनुमति दे दी है। यह कदम म्युचुअल फंड उद्योग की तरफ से सेबी को किए गए अनुरोध और आरबीआई की तरफ से डेट मार्केट का समय घटाने के निर्देश की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। दोनों ही कदम कोविड-19 के प्रसार और मौजूदा लॉकडाउन के कारण उठाए गए हैं।

म्युचुअल फंड सलाहकारों के मुताबिक, इस कदम से इक्विटी योजनाओं के निवेशकों को अपने नए आवंटन या निवेश निकासी सक्षम तरीके से करना मुश्किल बना देगा। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, इक्विटी योजनाओं के लिए कट-ऑफ समय दो घंटे पहले करने से थोड़ी असुविधा होगी। लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के कारण यह कदम अस्थायी है। डिजिटल चैनलों से निवेशकों को निवेश का फैसला तेजी से लेने में मदद मिलेगी।

उस दिन के एनएवी के लिए इक्विटी योजनाओं के निवेशकों को एक बजे से पहले निवेश करना होगा

इक्विटी बाजार 3.30 बजे बंद होता है, जिससे इक्विटी निवेशकों के लिए कट-ऑफ टाइम 3 बजे करना सुविधाजनक था। निवेश निकासी के लिए भी सभी योजनाओं में कट-ऑफ टाइम एक बजे कर दिया गया है।

बाजार नियामक ने म्युचुअल फंड उद्योग को इस बदलाव की सूचना दी और कहा कि यह फैसला आरबीआई की तरफ से डेट मार्केट की समयसारणी में बदलाव के बाद लिया गया है और इस बारे में म्युचुअल फंडों ने अनुरोध भी किया था। म्युचुअल फंड उद्योग ने पिछले हफ्ते सेबी को पत्र लिखकर कट-ऑफ टाइम बदलने की मांग की थी क्योंकि मौजूदा लॉकडाउन ने कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचना मुश्किल बना दिया था।

फ्लिपकार्ट और उबर ने मिलाया हाथ

पीरजादा अबरार और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 6 अप्रैल

मौजूदा देशबंदी के बीच जरूरी वस्तुओं तक लोगों की पहुंच के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली उबर ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। कंपनियों ने शुरू में बेंगलूरु, मुंबई और नई दिल्ली में सेवाएं शुरू की है।

यह साझेदारी अहम आपूर्ति शृंखला को बनाए रखेगी और फ्लिपकार्ट के ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना उनके घर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। कोविड-19 के प्रसार पर लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से किए गए लॉकडाउन में भी इस कदम से मदद मिलेगी ताकि लाखों भारतीय एक दूसरे से अलग रहें और महामारी को दूर रख पाएं।

उबर के निदेशक (परिचालन) और उबर इंडिया व दक्षिण एशिया प्रमुख प्रभजीत सिंह ने कहा, इस साझेदारी से अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने और सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक लोगों को घरों में रहने में मदद मिलेगी।

कोटक बैंक की जमा 20 फीसदी बढ़ी

निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि मार्च 2020 में समाप्त तिमाही के दौरान उसका जमा आधार 20 फीसदी बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का यह आंकड़ा 2.16 लाख करोड़ रुपये रहा था। पिछली तिमाही यानी दिसंबर 2019 तिमाही के मुकाबले बैंक के जमा आधार में 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान बैंक का कुल अग्रिम 6.7 फीसदी बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 2.05 लाख करोड़ रुपये रहा था। क्रमिक आधार पर बैंक ने अग्रिम में 1.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को जमा और अग्रिम के आंकड़ों की जानकारी दी और कहा कि ये आंकड़े वैधानिक अंकेक्षण के अधीन हैं। मार्च तिमाही यानी वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में बैंक के चालू एवं बचत खातों का अनुपात (सीएएसए) 56.2 फीसदी हो गया जो वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में 52.5 फीसदी और वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 53.7 फीसदी था। बैंक के बचत खाते में जमा राशि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 31 फीसदी बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि चालू खाते की जमा रकम में 10.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

डिस्क्लेमर: बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा लि में कोटक परिवार द्वारा नियंत्रित उपक्रमों की उल्लेखनीय हिस्सेदारी है।

हवाई टिकटों पर नहीं मिल रहा रिफंड

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 6 अप्रैल

अमृता वर्ष 2019 के मध्य में अपनी पहली नौकरी मिलने के बाद से ही कैलिफोर्निया घूमना चाहती थीं। उन्होंने अपनी तैयारी की और वेगास यात्रा की योजना बनाई। लेकिन कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया। इससे टिकट बुकिंग पर खर्च की गई उनकी रकम अटक गई। उन्होंने अप्रैल की अपनी यात्रा के लिए दिसंबर में टिकटों की बुकिंग पर 42,500 रुपये खर्च किए थे।

एतिहाद एयरलाइंस ने उन्हें रकम वापस करने से इनकार कर दिया और बराबर रकम का वाउचर दिया जिसका उपयोग अगले साल 31 जुलाई तक किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में इस वायरस का प्रकोप काफी गंभीर हो चुका है और ऐसे में फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि अमृता निकट भविष्य में कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा करेंगी। अब वह रोजाना करीब 10 मिनट तक विमानन कंपनी से बातचीत में गुजारती हैं ताकि रकम वापस मिल सके।

पच्चीस वर्षीय अमृता ने कहा, 'मैंने उन्हें फोन किया लेकिन वे रोबोट हैं और एक ही जानकारी बार-बार दोहराते हैं कि एतिहाद ने रिफंड न देने और उसके बदले वाउचर देने का निर्णय लिया है।'

- हवाई यात्रियों को रिफंड नहीं दे रहीं विमानन कंपनियां
- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उड़ानों को रद्द किया गया लेकिन अंतरराष्ट्रीय और भारतीय विमानन कंपनियां यात्रियों को नकदी लौटाने के बजाय दे रहीं क्रेडिट

ऐसा केवल अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी के मामले में नहीं हो रहा है बल्कि घरेलू विमानन कंपनियों की भी यही कहानी है। भारतीय विमानन कंपनियां भी यात्रियों को रिफंड देने से इनकार कर रही हैं। वे भी उन्हें क्रेडिट दे रही हैं जिसका उपयोग बाद में किया जा सकता है। विमानन कंपनियों पर ग्राहकों का लाखों रुपये का बकाया है और ऐसे में विमानन कंपनियों के बेलआउट पर करदाताओं की रकम खर्च करने के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जबकि ये विमानन कंपनियां उन्हीं करदाताओं के बकाये को वापस करने से इनकार कर रही हैं।

भारतीय नागरिक उड्डयन नियामक के निर्देशों के अनुसार, उड़ान रद्द होने की स्थिति में विमानन कंपनी यात्रियों को रकम लौटाने के लिए बाध्य है। लेकिन खराब मौसम जैसी कुछ परिस्थितियां इसके अपवाद हैं। नागर विमानन मंत्रालय के चार्टर में कहा गया है, 'यदि आपको उड़ान रद्द होने की सूचना दो सप्ताह से कम समय में लेकिन निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे तक दी जाती है तो विमानन कंपनी को दूसरी उड़ान की पेशकश करनी चाहिए अथवा टिकट की रकम वापस करनी चाहिए।'

एक विमानन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ऐसा सामान्य परिस्थिति में होता है। लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कई सप्ताह तक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है जिससे नकदी और राजस्व बचाना विमानन कंपनियों की मजबूरी हो गई है। यदि अब उन्हें रिफंड देने के लिए मजबूर किया जाता है तो कई विमानन कंपनियों को कारोबार से बाहर होना पड़ेगा।' इंटरनैशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) की आधिकारिक टिप्पणी से भी यही बात उजागर होती है। आईएटीए ने शुक्रवार को सरकार से आग्रह किया कि बुकिंग रद्द होने पर रिफंड संबंधी नियमों में ढील दी जाए।

आईएटीए ने कहा, 'हमारा मानना है कि विमानन कंपनियों और ट्रैवल एजेंट दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका नियामकीय जरूरतों में ढील देते हुए विमानन कंपनियों को नकद रिफंड के बजाय वाउचर जारी करने की अनुमति देना होगा। इससे एजेंट पर नकद रिफंड करने का दबाव ऐसे समय में कम होगा जब विमानन कंपनियों को अपनी जरूरत के लिए नकदी बचाने की बेहद आवश्यकता है।'

हालांकि उनके ग्राहक इसकी शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उड़ान रद्द होने के बावजूद उन्हें टिकट बुकिंग की रकम वापस नहीं मिल पा रही है।

डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि नकद रिफंड के बदले वाउचर जारी करने संबंधी आईएटीए के सुझाव पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा, 'हम इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। लेकिन इस संबंध में हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा क्योंकि हमें यात्रियों और विमानन कंपनियों दोनों को बचाना है।'

जिनके पास ज्यादा नकदी, उनमें दिख रही मजबूती

मांग में गिरावट के दौरान सुरक्षा कवर का काम कर सकती है मजबूत नकदी स्थिति

विशाल छाबड़िया और राम प्रसाद साहू

पिछले महीने के दौरान प्रमुख सूचकांकों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई और फरवरी के अंत में शुरू हुआ कमजोरी का रुझान बरकरार रहने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई चुनौती से व्यावसायिक गतिविधि ठहर गई है और बिक्री जैसे आंकड़ों में इसका स्पष्ट असर दिखा है। वाहन बिक्री की रफ्तार थम गई है।

अचानक पैदा हुई इस समस्या से मूल्यांकन में भारी गिरावट आई है। जहां निफ्टी के लिए पिछला कीमत-आय अनुपात 6 साल के निचले स्तर पर है, वहीं प्राइस-टु-बुक वैल्यू पिछले 11 वर्षों में सबसे नीचे है। हालांकि सभी क्षेत्रों के मूल्यांकन में बड़ी कमजोरी आई है और अनिश्चितता तथा राजस्व में सीमित संभावना को देखते हुए बाजार विश्लेषकों ने 'सबसे पहले सुरक्षा' का दृष्टिकोण अपनाया है।

गिरावट और मांग में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम करने का एक तरीका नकदी संपन्न कंपनियों पर ध्यान देना है। विश्लेषकों का मानना है कि नकदी संपन्न कंपनियां राजस्व पर दबाव, लागत में वृद्धि, और मांग में गिरावट का सामना करने में अन्य कंपनियों की तुलना में ज्यादा मजबूती के साथ सक्षम होंगी। जहां सभी कंपनियों को मांग पर दबाव का सामना करना पड़ेगा, वहीं अपने संबद्ध उद्योगों में मजबूत दबदबा रखने वाली और शानदार बैलेंस शीट वाली कंपनियां बेहतर तरीके से इस चुनौती का मुकाबला कर सकेंगी। वह हालात सामान्य होने की स्थिति में वृद्धि के अवसरों का तेजी से फायदा उठाने में भी आगे रहेंगी।

मोतीलाल ओसवाल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रमुख मनीष संथालिया ने कहा, 'यह सुनामी कई कंपनियों को बरबाद करेगा। इस हालात से अच्छी तरह से मुकाबले के लिए कंपनी को पर्याप्त नकदी और पूंजी तक पहुंच बनाने की जरूरत होगी और उसे अपना कर्ज स्तर शून्य बनाए रखना होगा।'

ऐसे में कई विश्लेषक निवेशकों के लिए नकदी संपन्न कंपनियों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं जो इस संदर्भ में चिंताजनक है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकट का असर अल्पावधि से परे हो सकता है। प्रभुदास लीलाधर के मुख्य कार्याधिकारी एवं मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर (पीएमएस) अजय बोडके का कहना है, 'लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सभी क्षेत्रों में खपत और मांग प्रभावित बनी रह सकती है। इसलिए नकदी संपन्न कंपनियां अपने परिचालन और निर्धारित लागत के प्रबंधन के लिहाज से बेहतर स्थिति में होंगी।' सोंथालिया का कहना है, 'कंपनियों को निरंतरता बनाए रखने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना होगा। यह ऐसी स्थिति है जिसमें नकदी हाथ में रखने की जरूरत होती है।'

बहीखाते में नकदी के अलावा, निवेशकों को ब्याज कवरेज और कैश बर्न रेशियो (कार्यशील पूंजी में बदलाव के बाद परिचालन नकदी प्रवाह) जैसे मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए।

कम कर्ज स्तर और मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह की जरूरत को देखते हुए ऐक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी एफएमसीजी, दूरसंचार और फार्मास्युटिकल कंपनियों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत बेहतर मांग देख रही हैं। वे बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र और रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कर्ज और नकदी प्रवाह के प्रबंधन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि विश्लेषक वैश्विक और घरेलू चक्रीयता से दूरी बनाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर या तो कर्ज, नकदी प्रवाह की समस्या या अनिश्चित विकास परिदृश्य का सामना करना पड़ता है। जहां कुछ विश्लेषको का मानना है कि सॉफ्टवेयर दांव अच्छा निर्णय हैं, वहीं जेपीमॉर्गन का मानना है कि यह क्षेत्र कोविड-19 की वजह से मांग पर संभावित दबाव को देखते हुए प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इसके प्रमुख बाजारों में अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल हैं। बोडके का कहना है कि निवेशकों को विमानन, होटल, मल्टीप्लेक्स, ट्रैवल, लगेज निर्माताओं और एनबीएफसी था बैंक जैसे क्षेत्रों की कंपनियों से परहेज करना चाहिए।

नकदी संपन्न कंपनियों तक पहुंचने के लिए, हमनें न सिर्फ कैश इक्विलंट्स (नकदी एवं बैंक बैलेंस के साथ साथ निवेश) पर ध्यान दिया बल्कि अतिरिक्त नकदी पर भी जोर दिया जो व्यवसाय अपने परिचालन खर्च के लिए लगातार अर्जित करते हैं। इसके अलावा, कर्ज स्तर को न्यूनतम बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए, कर्ज-पूंजी अनुपात 0.5 से कम समझा गया था। इसके अलावा, 20 प्रतिशत से कम आरओई वाली कंपनियों को भी अलग रखा गया। ताजा गिरावट में निवेशकों ने भी उन कंपनियों में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनकी आय के लिए जोखिम कम रहा, मजबूत नकदी स्थिति रही। एचडीएफसी सिक्योरिटी में पूंजी बाजार रणनीति के प्रमुख विनोद शर्मा कहते हैं, 'नकदी संपन्न कंपनियां मौजूदा बाजार हालात के लिए अनुकूल हैं। जब बाजार हालात खराब हैं, अतिरिक्त नकदी वाली कंपनियों के शेयरों में कम अंतर से गिरावट आती है और जब बाजार में सुधार आता है तो इनमें तेजी की गति मजबूत होती है।' कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। निवेशकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे जो शेयर खरीदने की सोच रहे हैं वे गिरवी न रखे हों।

नकदी संपन्न कंपनियां

कंपनी	सीएमपी रुपये	नकद (प्रतिशत)	पीबीटी (प्रतिशत)	नकद करोड़ रुपये
ऑरिक्कल फाइनैंस	2,039	107.2	9.5	3,681
आईटीसी	178	93.7	10.0	2,990
डॉ लाल पैथ	1,339	78.1	13.9	775
ऐबट इंडिया	15,827	56.9	21.9	1,813
नेस्ले इंडिया	15,151	47.1	10.1	3,059
इन्फोसिस	585	45.7	5.0	17,288
आईजीएल	407	44.1	23.3	804
टीसीएस	1,654	40.6	6.1	43,136
टेक महिंद्रा	521	30.6	0.0	8,237
कैस्ट्रॉल	102	27.1	4.4	946

स्रोत- कैपिटालाइन, संकलन- बीएस रिसर्च

बाजार हलचल

नाजुक मोड़ पर पहुंचा निफ्टी

शुक्रवार को निफ्टी 8,084 के स्तर पर बंद हुआ जो 24 मार्च से इसका सबसे निचला स्तर है। टेक्नीकल विश्लेषकों का कहना है कि 50 शेयर वाला यह सूचकांक समर्थन स्तर के आसपास अटका हुआ है। एक विश्लेषक ने कहा कि यदि निफ्टी 8,000 पर बना रहा तो यह चढ़कर 8,300 पर जा सकता है। यदि यह इससे नीचे गिरता है तो पुन: 7,600 के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। बाजार कारोबारियों का कहना है कि इंडिया वीआईएक्स में स्थिरता सकारात्मक है, क्योंकि अल्पावधि में इसमें कम अस्थिरता का संकेत मिलता है। पिछले सप्ताह बाजार में अस्थिरता का मापक यह सूचकांक काफी गिर गया था, क्योंकि निफ्टी में भी 6.5 प्रतिशत की कमजोरी आई थी। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि वित्तीय शेयरों में कमजोरी बाजार के लिए मुख्य समस्या है। *– समी मोडक*

ईटीएफ पर गिरावट का ज्यादा असर नहीं

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का मकसद सूचकांक के समान प्रतिफल देना है, लेकिन ताजा बाजार अनिश्चितता के बीच इसमें ट्रैकिंग संबंधी असमानता दिख रही है। उद्योग के जानकारों के अनुसार, बाजार में तेज उतार-चढ़ाव ने ईटीएफ में तरलता की कमी को उजागर किया है। एक ब्रोकिंग फर्म के प्रमुख ने कहा, 'ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब निफ्टी ईटीएफ दिन के कारोबार के दौरान सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करने में सक्षम नहीं रहा। इंट्रा-डे सत्रों के दौरान जब निफ्टी 6-7 प्रतिशत गिरा, तो ईटीएफ की कीमत सकारात्मक दायरे में दिखी। इसी तरह, जब निफ्टी में 4-5 प्रतिशत तक की तेजी आई, ईटीएफ में इंट्रा-डे कारोबार में इस तरह की बढ़त नहीं देखी गई।' उन्होंने कहा, 'खासकर ज्यादा उतार-चढ़ाव की अवधि में इन निवेश विकल्पों में कारोबार को समर्थन प्रदान करने के लिहाज से एक्सचेंजों पर पर्याप्त कारोबारी मौजूद नहीं हैं। सिर्फ दिन के अंत में, ईटीएफ की एनएवी दिन के बंद भाव के आधार पर समायोजित होती है।' – *जश कृपलानी*

ब्रोकिंग इंडस्ट्री में छंटनी का खतरा गहराया

बाजार में भारी गिरावट और घरेलू आर्थिक गतिविधि में अचानक कामकाज ठप होने से ब्रोकिंग उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि बड़े ब्रोकर रोजगार और वेतन कटौती की तैयारी कर रहे हैं। इस उद्योग के एक जानकारी ने कहा, 'यह ब्रोकिंग उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। कई ब्रोकरों को ऊंची परिचलन लागत और पारिश्रमिक खर्च का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों को नकदी संकट से जूझना पड़ रहा है क्योंकि कारोबार की मात्रा काफी घट गई है और परिसंपत्ति कीमत में गिरावट से कॉलेटरल वैल्यू प्रभावित हुई है। अस्थिरता में वृद्धि से कारोबारी आक्रामक दांव लगाने से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा, कोष का संग्रह भी लॉकडाउन की वजह से चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई ब्रोकरेज कंपनियों के पास वेतन कटौती या छंटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है।' – *समी मोडक*

एसआईपी योजनाएं प्रभावित होने का खतरा

जश कृपलानी

देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधि ठप पड़ने से म्युचुअल फंड (एमएफ) निवेशकों को अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट योजनाओं (एसआईपी) को बंद करने या रोकने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से निवेशकों की मासिक आय पर दबाव पड़ने की आशंका गहरा गई है।

सलाहकारों का कहना है कि निराशाजनक इक्विटी प्रतिफल और आय में कमी की आशंका से निवेशकों को एसआईपी रोकने का कदम उठाना पड़ रहा है। प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, 'वैश्विक घटनाक्रम से ज्यादा प्रभावित हुए एयरलाइन और होटल जैसे क्षेत्रों से जुड़े ग्राहकों को अपने एसआईपी खर्च पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसके अलावा, कुछ निवेशकों को इस अवधि के दौरान वेतन कटौती का सामना करना पड़ा है।'

शेयर बाजार में गिरावट से एमएफ निवेशकों का प्रतिफल प्रभावित हुआ है। फरवरी में 6 प्रतिशत गिरने के बाद, सेंसेक्स ने मार्च में 23 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। अनुमानों से पता चला है कि 85-90 प्रतिशत एसआईपी निवेशक इक्विटी परिसंपत्तियों से जुड़े हुए हैं।

मुंबई स्थित तेजस कंसल्टेंसी के सह-संस्थापक रितेश शेठ ने कहा, 'आगामी नकदी प्रवाह को लेकर सभी तरह के ग्राहकों में अनिश्चितता है, चाहे वे वेतन-भोगी हों या स्व-रोजगार से जुड़े हुए हों। उनका मानना है कि फिलहाल एसआईपी को रोकना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ऋण ईएमआई जैसी देनदारियां चुकाना मौजूदा परिवेश में प्राथमिकता बन गई है।'

मार्च का एसआईपी प्रवाह प्रभावित नहीं होने की संभावना है, लेकिन अप्रैल के आंकड़े एमएफ उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक फंड हाउस के अधिकारी ने कहा, 'हमें मार्च में 8,000-8,200 करोड़ रुपये के एसआईपी प्रवाह का अनुमान है, लेकिन अप्रैल के आंकड़े पर दबाव देखा जा सकता है।'

लगभग 27 लाख करोड़ रुपये के एमएफ उद्योग को देखते हुए एसआईपी से मजबूत प्रवाह अब तक निवेशक परिसंपत्तियों का नियमित माध्यम है, भले ही हाल के महीनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा हो।

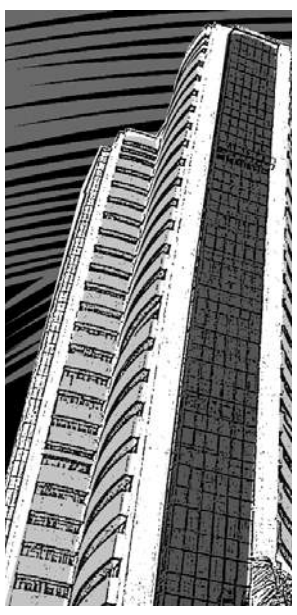

■ निवेशकों की मासिक आय पर दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है

फरवरी में, एसआईपी प्रवाह पूर्ववर्ती महीने के मुकाबले 8,513 करोड़ रुपये पर मजबूत बना हुआ था।

एमएफ सलाहकारों का कहना है कि जहां कुछ नकदी किल्लत वाले ग्राहक अपने एसआईपी बंद करना या रोकना चाहते हैं, वहीं उन्हें एमएफ की ऑफलाइन शाखाओं में इस संबंध में अनुरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये शाखाएं अभी बंद हैं।

एक एमएफ वितरक ने कहा, 'सभी एमएफ के पास एसआईपी बंद करने या रोकने के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद नहीं है।'

सूत्रों के अनुसार, बाजार नियामक सेबी ने 44 कंपनियों वाले एमएफ उद्योग से एसआईपी बंद करने की सुविधा अपनी वेबसाइटों पर तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे कि निवेशक अपने अनुरोध आसानी से देने में सक्षम हो सकें।

अगस्त और सितंबर 2019 में 66 प्रतिशत की वृद्धि के बाद एसआईपी बंद होने का अनुपात अब 50 प्रतिशत के आंकड़े के आसपास है। फरवरी में यह 50.4 प्रतिशत था, जिसका मतलब है कि प्रत्येक दो नए एसआईपी खातों में से एक को बंद कराने का अनुरोध दिया गया है। वहीं, एसआईपी कुछ समय के लिए रोकने के विकल्प के तहत एमएफ निवेशक अस्थायी तौर पर अपने मासिक एसआईपी निवेश को बंद कर सकता है, लेकिन एसआईपी रद्द किए जाने के बाद इसे पुन:पंजीकृत कराने की जरूरत होगी।

ओएमसी को राहत: कच्चे तेल में गिरावट से मदद मिलेगी

एचपीसीएल को विपणन मार्जिन में सुधार से अन्य कंपनियों के मुकाबले ज्यादा लाभ मिल सकता है

उज्ज्वल जौहरी

बाजार में गिरावट के बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल (आईओसी) जैसी सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के शेयरों में अपने 2020 के ऊंचे स्तरों से 30-40 प्रतिशत की कमजोरी आई है। हालांकि इन कंपनियों के लिए सकारात्मक बदलाव भी आया है। कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 18 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं जिससे इन कंपनियों को दीर्घावधि के संदर्भ में संभावनाएं मजबूत हुई हैं। ओएमसी के शेयर हाल में 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद पिछले दो कारोबारी सत्रों में फिर से 15 प्रतिशत तक चढ़ गए थे।

नकारात्मक खबर यह है कि तेल कीमतों में ताजा गिरावट और लॉकडाउन की वजह से मांग में कमी से इन्वेंट्री नुकसान (कच्चे तेल और उत्पादों पर) के साथ साथ मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा, और इस वजह से ओएमसी की अल्पावधि आय प्रभावित होगी। सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषकों को कमजोर मार्जिन, इन्वेंट्री नुकसान, मांग में कमी आदि को देखते हुए चौथी तिमाही में ओएमसी के परिचालन एवं शुद्धलाभ में 66-86 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका हैं

वहीं अच्छी खबर यह है कि इन नकारात्मक घटनाक्रम का प्रभाव अब शेयर कीमतों पर दिख चुका है। आय में कटौती के बावजूद सेंट्रम ब्रोकिंग ने तीन ओएमसी के शेयरों के लिए सस्ते मूल्यांकन की वजह से खरीदारी की रेटिंग दी है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमजोरी इन कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे उनके विपणन मार्जिन में वृद्धि, कार्यशील पूंजी जरूरतों में कमी और सब्सिडी बोझ के खतरे में कमी लाने में मदद मिलेगी। सरकार को भी केरोसिन और कुकिंग गैस कीमतों को लकर कई और सुधार लाने का अवसर मिलेगा, जो ओएमसी के लिए सकारात्मक होगा।

इस वजह से अल्पावधि चिंताओं को दरकिनार करते हुए विश्लेषकों का कहना है कि ओएमसी वृद्धि के लिहाज से अच्छी स्थिति में बनी रहेंगी, क्योंकि लॉकडाउन समाप्त होने पर इनके लिए मांग बढ़ने की संभावना है। विपणन मार्जिन (पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर) का परिदृश्य भी मजबूत बना हुआ है। रिलायंस सिक्योरिटीज के योगेश पाटिल का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में प्रति 1 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट की वजह से ओएमसी के शुद्ध विपणन मार्जिन में 0.45 रुपये प्रति लीटर (45 पैसे) तक का इजाफा होता है। हालांकि सरकार द्वारा खुदरा ईंधन पर शुल्क बढ़ाए जाने की स्थिति में यह मार्जिन कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है।

कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 18 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं

कोटक सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि डीजल और गैसोलिन पर सकल खुदरा विपणन मार्जिन (प्रति लीटर आधार पर)का उनका अनुमान 27 मार्च 2020 को एक सप्ताह पहले के 8.1 रुपये और 7.1 रुपये से सप्ताह-दर-सप्ताह बढ़ाकर 11.8 रुपये और 13.3 रुपये कर दिया गया। सकारात्मक संदर्भ में, प्रमुख पॉलिमर के लिए भी मार्जिन हाल के सप्ताह में बढ़ा है। नाफ्था और गैस कीमतों में गिरावट की वजह से इस मार्जिन में इजाफा हुआ है।

एडलवाइस का कहना है कि वैश्विक रूप से जीआरएम में तेज गिरावट आई है और भारत में रुझान समान बना हुआ है। हालांकि ओएमसी का खुदरा ईंधन मार्जिन बढ़ा है, और इससे कमजोर बिक्री और कमजोर सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) की भरपाई हुई है।

उनका कहना है, 'हमारा मानना है कि वित्त ओएमसी की वर्ष 2021 की अनुमानित आय में हमारा 12-21 प्रतिशत कटौती का अनुमान फिलहाल पर्याप्त है। दरअसल, हम मान रहे हैं कि भारतीय रिफाइनरियां दीर्घावधि में मजबूत स्थिति में होंगी, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाएंगी।' वित्त वर्ष 2021 के अनुमानों में कटौती के बावजूद ओएमसी के लिए 20-75 प्रतिशत की आय वृद्धि का संकेत दिख रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि तीनों कंपनियों में एचपीसीएल की कुल राजस्व में खुदरा बिक्री की सबसे ज्यादा भागीदारी है और वह विपणन मार्जिन के लिए बेहतर परिदृश्य से लाभान्वित होने के लिहाज से मजबूत स्थिति में है। यह शेयर पिछले दो कारोबारी सत्रों में 10 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है, जबकि आईओसी के शेयर ने इस अवधि में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एचपीसीएल की तुलना में आईओसी के लिए चिंताएं ज्यादा हैं।

बीएस बातचीत

यदि वित्त वर्ष 2021 में आय बढ़ी तो यह आश्चर्य होगा

मेबैंक किम इंग सिक्योरिटीज के मुख्य कार्याधिकारी **जिगर शाह** ने **पुनीत वाधवा** के साथ कोविड-19 की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के प्रभाव को लेकर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उद्योग को 14 अप्रैल के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। धीरे धीरे जब आपूर्ति श्रृंखला पटरी पर आएगी और मांग बढ़ेगी, क्षमता इस्तेमाल भी फिर से सामान्य हो सकता है। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

क्या मजबूत होने से पहले बाजार में और गिरावट आ सकती है?

यह एक अलग तरह की गिरावट है जिससे रियल और फाइनैंशियल अर्थव्यवस्था, दोनों पर प्रभाव पड़ा है। इस अप्रत्याशित गिरावट से पहले मूल्यांकन अमेरिका और कई अन्य बाजारों में सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर थे। प्रमुख सूचकांकों में इस साल अब तक (वाईटीडी) गिरावट 2008 के मुकाबले कम है, लेकिन इस गिरावट की गति काफी तेज है। बाजार पूंजीकरण का नुकसान काफी ज्यादा है। अब और अधिक गिरावट इस पर निर्भर करेगी कि कोरोनावायरस का संकट मई-जून 2020 के बाद बना रहता है या नहीं।

क्या बाजार में 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की आशंका का प्रभाव दिख रहा है?

अब तक व्यवसायों और उद्योग का यही मानना है कि 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे बाजार खुलने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा और फिर मांग बढ़ेगी, जिससे क्षमता इस्तेमाल भी सामान्य हो सकेगा। यह सितंबर तिमाही के अंत में हो सकता है, और उसके बाद मजबूत सुधार अक्टूबर-मार्च की अवधि में देखा जा सकेगा।

अगले कुछ महीनों में हम सेंसेक्स और निफ्टी के लिए किस तरह की चुनौतियां देख सकते हैं?

कॉरपोरेट आय पर मात्रा की दृष्टि से प्रभाव का आकलन करना कठिन है, लेकिन निफ्टी की एक साल आगे की आय के संदर्भ में 20 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि का ब्लूमबर्ग का अनुमान पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में निफ्टी के लिए प्राइस-टु-अर्निंग (पीई) 13-14 गुना था, जो पिछले 12 महीने के आधार पर अभी भी 19 गुना पर है। इस तरह से यदि, कोविड-19 को लेकर स्थिति और ज्यादा नाजुक होती है तो बाजार में गिरावट बढ़ जाएगी।

सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

आरबीआई और अन्य केंद्रीय बैंक दरों में कटौती, अतिरिक्त नकदी डालने, और विदेशी मुद्रा की स्थिति के प्रबंधन में सहायक बने हुए हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से इक्विटी में गिरावट के बावजूद रुपया अब तक काफी हद तक अनुकूल बना हुआ है।

जहां तक भारत का सवाल है, विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी कैसी है?

एफआईआई ने सभी उभरते बाजारों में बिकवाली की है और भारत इससे अलग नहीं है। ज्यादातर बिकवाली फंडों और पेंशन फंडों द्वारा की गई है। ऐसा रिडम्पशन के दबाव या असाधारण समय में नकदी पैदा करने की नीति की वजह से हो सकता है। बाजार में गिरावट से निवेशकों के लिए व्यापक अवसर पैदा हुए हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां बेहद कम मूल्यांकन पर मौजूद हैं, जो अक्सर नहीं देखने को मिलता है। यदि वैश्विक और स्थानीय वृहद परिदृश्य में सुधार होता है तो विदेशी प्रवाह सितंबर 2020 के बाद से फिर सकारात्मक हो सकता है।

वित्त वर्ष 2021 के लिए हम कॉरपोरेट आय पर कितना दबाव देखेंगे?

फिलहाल इस बारे में सटीक आंकड़ा बताना संभव नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2021 के लिए 200 आधार अंक तक घटाया गया है। वित्त वर्ष 2022 में आय वृद्धि देखी जा सकती है। वित्त वर्ष 2021 में आय में सुधार सकारात्मक रूप से आश्चर्य होगा।

लॉकडाउन के बावजूद दलाल पथ एफएमसीजी और दूरसंचार क्षेत्रों पर उत्साहित है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

हां, क्योंकि इन दो क्षेत्रों को अन्य के मुकाबले कम दबाव का सामना करना पड़ा है। दूरसंचार, मुख्य रूप से कोविड-19 से प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घरों में डेटा की मांग की मांग बढ़ रही है। मध्यावधि में खपत वृद्धि दर को लेकर चिंता है, क्योंकि संकट से पहले, यह तीन साल पहले के 16 प्रतिशत के मुकाबले घटकर महज 5-6 प्रतिशत रह गई थी। कोविड-19 प्रभाव की वजह से, वृद्धि दर कमजोर बनी रहेगी और अच्छी एफएमसीजी कंपनियों का पीई अनुपात अल्पावधि में सकारात्मक नहीं दिख रहा है।

क्या आप अगली कुछ तिमाहियों में बैंकों और एनबीएफसी के एनपीए में वृद्धि की आशंका जता रहे हैं?

पूरा वित्तीय क्षेत्र कोविड-19 महामारी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

थोक बाजार में सीजन के सबसे निचले भाव पर प्याज

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 6 अप्रैल

खरीफ की देर से तैयार होने वाले प्याज को लेकर किसान बड़ी संख्या में बाजार में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से लासलगांव की विनचुर मंडी में में इसकी कीमतें सीजन के निचले स्तर 3 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गईं हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में देश में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन होता है और इसका एशिया का सबसे बड़ा हाजिर बाजार लासलगांव में है। प्याज के दाम इस समय उत्पादन लागत से कम हो गए हैं।

मंडी में निर्यात की गुणवत्ता वाले प्याज के दाम 9 रुपये किलो हैं, वहीं इसके औसत दाम 6 रुपये प्रति किलो हैं, जो खरीफ और रबी फसल सीजन का निचला स्तर है। किसान खासकर खरीफ की देर वाली किस्म को बेचने की जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं क्योंकि यह किस्म जल्दी खराब हो जाती है। देशबंदी के कारण भोजनालयों के साथ होटल व रेस्टोरेंट, खासकर सड़क के किनारे के ढाबे बंद हो जाने की वजह से प्याज के मांग में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आई है।

मानक लासलगांव मंडी 4 दिन से बंद है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने कोविड-19 के मरीज को पिछले सप्ताह एकांतवास में भेजने के साथ पूरे तालुके को घर में रहने का आदेश दिया था। प्रशासन ने बाजार यार्ड सहित किसी भी जमावड़े से बचने के लिए यह कदम उठाया है, जिससे कि बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सके।

लासलगांव एपीएमसी के सचिव नरेंद्र वाधवाने ने कहा, 'किसान खासकर देर से तैयार होने वाली खरीफ किस्म की बिक्री को लेकर जल्दबाजी में हैं, क्योंकि उन्हें प्याज खराब हो जाने का डर है। ज्यादातर बाजार के यार्ड बंद हैं, इसलिए किसान विनचुर मंडी में प्याज ला रहे हैं। परिणामस्वरूप प्याज के औसत दाम गिरकर 6 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। खराब गुणवत्ता के प्याज की कीमत 3 रुपये किलो है, वहीं निर्यात की गुणवत्ता वाला प्याज विनचुर कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) में सोमवार को 9 रुपये किलो बिका।'

विनचुर मंडी में प्याज की कुल आवक अप्रत्याशित रूप से बढ़कर सोमवार को 2400 टन हो गई, जो सामान्य दिनों में होने वाली आपूर्ति की तुलना में दोगुना है।

देशबंदी के कारण राज्य में और राज्य के बाहर परिवहन सीमित है। प्याज आवश्यक जिंस की श्रेणी में है, इसलिए इसकी ढुलाई जारी है, लेकिन इसकी भी आवाजाही सीमित है। दिलचस्प है कि विदेश से इसकी मांग कम होने की वजह से निर्यात भी ठहर गया है। आयात करने वाले देश भी कोविड 19 से जूझ रहे हैं, ऐसे में भारत से प्याज निर्यात हाल फिलहाल में सामानन्य होने की संभावना कम है।

नासिक एपीएमसी के सचिव अरुण काले ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से प्याज के दाम में तेज गिरावट हो रही है। नासिक में प्याज की आवक बंपर है, जहां से देश भर में आपूर्ति होती है। इस समय हम गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में प्याज की आपूर्ति कर रहे हैं।'

नासिक मंडी में सोमवार को खराब गुणवत्ता (छोटे आकार व कुछ खराब) और बेहतर गुणवत्ता का प्याज सोमवार को 6.50 रुपये प्रति किलो और 12 से 13 रुपये प्रति किलो बिका। खुदरा में इस समय प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा है क्योंकि देशबंदी की वजह से आपूर्ति बाधित है। लेकिन मौजूदा थोक भाव का असर अगले 7 से 10 दिन में खुदरा कीमतों पर नजर आने लगेगा।

प्याज के किसान इस समय बहुत तनाव में आ गए हैं क्योंकि वे खेती की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बीज, सिंचाई और श्रम लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे नासिक के ज्यादातर इलाके में प्याज का उत्पादन लागत 5.50 से 6 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां उत्पादन लागत 7 से 8 रुपये किलो है।

वाधवाने ने कहा, 'किसानों को उतना भी नहीं मिल रहा है, जितनी लागत उन्हें प्याज की फसल तैयार करने में लगी है। छोटे और मझोले प्याज किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं होती और वे सार्वजनिक गोदामों में भंडारण की लागत वहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे में उनके पास उत्पाद बेच देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह के तनाव की स्थिति का लाभ बड़े कॉर्पोरेट, स्टॉकिस्ट और गोदाम मालिक उठा रहे हैं और सस्ता प्याज खरीदकर भंडारण कर रहे हैं।'

प्याज 3 रुपये किलो

- महाराष्ट्र की विनचुर मंडी में खरीफ सीजन का प्याज 3 रुपये किलो पहुंचा
- किसान की उत्पादन लागत 6 से 8 रुपये प्रति किलो, इससे कम भाव पर प्याज
- आयात मांग भी कम, आयातक देश भी कोरोना के संकट से जूझ रहे
- छोटे और मझोले किसानों के पास भंडारण सुविधा न होने का लाभ उठा रहे कॉर्पोरेट, स्टॉकिस्ट और गोदाम मालिक

मार्च में सेवा गतिविधियां सुस्त

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 6 अप्रैल

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस ने भारत के सेवा क्षेत्र के अच्छे दिन कम कर दिए हैं। विदेश से मांग घटने और निर्यात घटने से सोमवार को जारी मासिक सर्वे में भारत का सेवा क्षेत्र सिकुड़ा नजर आ रहा है।

निक्केई इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी महीने की तुलना में 7 अंक से ज्यादा गिरकर मार्च में 49.3 रह गया है। फरवरी में यह 7 साल के उच्च स्तर 57.5 पर था। पीएमआई के आंकड़ों में 50 अंक से ऊपर कारोबार का विस्तार और उससे नीचे संकुचन दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना था कि फरवरी में सेवा क्षेत्र का कारोबार 85 महीने के उच्च स्तर पर रहा है, जिससे कोरोना के संकट से आए तूफान को थामने में मदद मिलेगी, नए विदेशी बाजारों से नए ऑर्डर बढ़ेंगे जिसे वृद्धि दर स्थिर रह सकेगी।

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस

लेकिन मार्च में सर्वे करने वाली फर्म ने कहा है कि ग्राहकों की मांग घट गई है, क्योंकि स्वास्थ्य वजहों से विवेकाधीन व्यय रुक गया है। यह विनिर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती की तर्ज पर हुआ है, जो मार्च महीने में गिरकर 4 महीने के निचले स्तर 51.8 पर पहुंच गया, जो फरवरी के 54.5 की तुलना में कम है। विनिर्माण क्षेत्र की रिपोर्ट निक्केई ने पिछले सप्ताह जारी की थी।

सितंबर 2014 के बाद से निर्यात सबसे तेज गिरा है। पूरे महीने के दौरान रुपये के गिरते रहने के बावजूद ऐसा हुआ है। मार्च की शुरुआत में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 72 पर था, जो एक अप्रैल को 76 रुपये पर पहुंच गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर ठहर गया है।

पीएमआई सर्वे में दिखाया गया है कि सेवा क्षेत्र की फर्में नौकरियों में मामूली कमी दिख रही है क्योंकि पेरोल पर काम करने वाले लोगों की संख्या में 93 प्रतिशत फर्मों ने कोई बदलाव नहीं किया है। यहां तक कि फरवरी के तेजी में भी नौकरियों के सृजन की संख्या गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर थी।

हाल के सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2019 के बाद से सेवा प्रदाताओं के ऑर्डर बुक की मात्रा में पहली बार गिरावट आई है। मांग में गिरावट 2 वर्षों की तुलना में सबसे तेज रही है। नकदी की कमी की वजह से कई फर्मों ने कम बिक्री की है।

सर्वे में कहा गया है कि इसके बावजूद क्षमता पर दबाव के कुछ साक्ष्य मिले हैं, हालांकि यह बहुत कम था। पिछले काम का दबाव बढ़ा था, लेकिन मार्च में स्थिति कमजोर रही। बहरहाल उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि मार्च में बहुत गिरावट हो सकती है। आईएचएस मार्किट के अर्थशास्त्री जो हाएस ने कहा, 'मार्च के पीएमआई के आंकड़े से पता चलता है कि कारोबारी गतिविधियां गिर रही हैं। बहरहाल सर्वे के आंकड़े 12 से 27 मार्च के हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशबंदी की घोषणा की थी।' लेकिन फर्मों को भरोसा है कि गतिविधियों का स्तर अगले 12 महीने में बड़ेगा क्योंकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और यह हटते ही वैश्विक मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि आत्मविश्वास का स्तर गिरकरक 5 महीने के निचले स्तर पर है।

फरवरी की तेजी के बाद मार्च में आई तेज गिरावट

- मार्च में पीएमआई सर्विस इंडेक्स 49.3 पर रहा, जो फरवरी में 85 महीनों के उच्च स्तर 57.5 पर था
- सर्वे के ये आंकड़े 12 से 27 मार्च के बीच जुटाए गए, देशबंदी की वजह से सेवा क्षेत्र की मांग में भारी कमी
- सितंबर 2019 के बाद सेवा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों की ऑर्डर बुक में मार्च में पहली बार गिरावट
- रुपये में तेज गिरावट के बावजूद निर्यात सितंबर 2014 के बाद सबसे तेज गिरा है

कोविड से सिकुड़ेगी अर्थव्यवस्था

अनूप रॉय
मुंबई, 6 अप्रैल

यूबीएस के मुताबिक कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था संकुचन की ओर बढ़ सकती है। यह वैश्विक महामारी की गंभीरता पर निर्भर होगा। वहीं यूबीएस का यह भी मानना है कि मंदी की स्थिति रिकॉर्ड कम समय तक रहेगी। यूबीएस में भारत की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी जैन गुप्ता ने कहा, 'अर्थव्यवस्था में मंदी देशबंदी की अवधि के मुताबिक होगी और आर्थिक नीति में बदलाव से सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित होगी।'

अगर आवाजाही पर प्रतिबंध की स्थिति को 1 से 10 के पैमाने पर देखें तो भारत 10 के स्तर पर आता है। चीन में आवाजाही पर प्रतिबंध 4 अंक के स्तर पर था। आवाजाही पर प्रतिबंध के हिसाब से भारत में लॉकडाउन अप्रैल के पहले पखवाड़े तक है और अगले एक हफ्ते तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जून तक सीमित आवाजाही रहने की संभावना है।

तन्वी गुप्ता जैन, अर्थशास्त्री

यूबीएस की अर्थशास्त्री ने कहा, 'अगर मई के मध्य तक स्थिति सामान्य होती है तो क्षति सीमित होगी और वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि 4 प्रतिशत रह सकती है।'

बहरहाल बहुत खराब स्थिति में अगर यह कल्पना करें कि सितंबर के अंत तक व्यवधान रहेगा, जिसमें 4 से 5 सप्ताह लॉकडाउन होगा और 7 से 8 सप्ताह तक सीमित आवाजाही रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, ऐसी स्थिति में जैन का माना है कि 'भारत में पहली बार वित्त वर्ष 1980 के बाद ऋणात्मक जीडीपी हो सकती है।' ऐसी स्थिति में वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था 0.2 प्रतिशत सिकुड़ सकती है।

किसी भी मामले में आर्थिक खपत बुरी तरह प्रभावित होगी और इसकी वजह से नौकरियां जाने और आमदनी घटने की संभावना है। इससे परिवारों का लेखा जोखा बिगड़ेगा क्योंकि आय पर दबाव बढ़ रहा है जबकि बचत तेजी से खत्म हो रही है। गुप्ता ने कहा कि करीब 30 प्रतिशत खपत सेवा से जुड़ी हुई है। देशबंदी और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण सेवा की यह मांग खत्म हो सकती है औक इस व्यवधान के दौरान खपत पूरी तरह से खत्म हो सकती है।

वित्त वर्ष-20 में बना 3,979 किमी राजमार्ग

मेघा मनचंदा
मुंबई, 6 अप्रैल

कोरोनावायरस फैलने के बीच सड़क निर्माण के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने वित्तवर्ष 2019-20 में 3,979 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण काम पूरा कर लिया है।

काम संतोषजनक

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'वित्त वर्ष 2019-20 में एनएचएआई ने 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का काम पूरा किया है। यह किसी भी वित्त वर्ष में एनएचएआई द्वारा किए गए काम की तुलना में सबसे ज्यादा है।'

प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में 4,500 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा था, जो प्रति दिन 12.32 किलोमीटर होता है। इस हिसाब से प्राधिकरण अपने लक्ष्य से चूक गया है और प्रति दिन निर्माण 10.9 किलोमीटर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक एनएचएआई ने आंतरिक रूप से प्रतिदिन सड़क निर्माण का कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। एनएचएआई ने कहा कि पिछले साल सड़क निर्माण में तेजी आई थी और वित्त वर्ष 2018-19 में 3,380 किलोमीटर निर्माण हुआ था। इसी धारणा को जारी रखते हुए एनएचएआई ने 2019-20 में 3,979 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है।

गिग वर्कर्स को मिल रहा काम, बढ़ रही कंपनियों की साझेदारी

नेहा अलावधी और समरीन अहमद
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 6 अप्रैल

कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए बंदी की अवधि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कंपनियों विशेष तौर पर गिग कर्मचारियों (ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारी) को रोजगार देने वाली कंपनियां अपने कारोबार को जारी रखने के लिए अभिनव साझेदारी करने पर विचार कर रही हैं। वे इस समय अपने गिग कर्मचारियों को अर्थपूर्ण तरीके से नौकरी करने का अवसर दे रही हैं।

पिछले हफ्ते स्टार्टअप कंपनियों, परंपरागत कारोबारों और अस्पतालों के बीच विभिन्न असामान्य साझेदारियों की घोषणा की गई। उसी तरह की कई और घोषणाएं जल्द ही की जाएंगी। कर्मचारियों की सेवा देने वाली कंपनी टीमलीज सर्विसेज के सहायक उपाध्यक्ष अमित वडेरा ने कहा, 'गिग कर्मचारियों को कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और अंशकालिक या स्थायी छंटनी से कर्मचारियों को सुरक्षित रखने की सरकार के परामर्शों के तहत उन्हें कवर नहीं किया जाता है। कंपनियां अब इस बारे में सोच रही हैं कि इन लोगों की आजीविका को कैसे बरकरार रखा जा सकता है।'

उदाहरण के तौर पर पिछले हफ्ते उबर ने दो नए बिजनेस टू बिजनेस साझेदारियों की घोषणा की थी। इनमें पहला है उबरमेडिक जो स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े अधिकारियों के लिए 24 घंटे की सेवा है। यह अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को उनके घर से लाने और ले जाने और चिकित्सा सुविधाओं के लिए परिवहन के साधन का इंतजाम करेगी।

दूसरी है बिगबास्केट जिसमें चार शहरों में ड्राइवर साझेदार अंतिम गंतव्य तक रोजाना के जरूरी सामान की आपूर्ति करने में सहयोग करेंगे। उसकी बेंगलूरु स्थित प्रतिस्पर्धी कंपनी ओला कैब्स कर्नाटक सरकार को 500 वाहन देने पर सहमत हुई है जिसका इस्तेमाल चिकित्सकों के परिवहन और कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में किया जाएगा। फ्लिपकार्ट साझेदारी के लिए गुंजाइश तलाश रही है। फिलहाल उसकी बातचीत कैब एग्रीगेटर्स और भारतीय रेलवे के साथ चल रही है ताकि विक्रेताओं से लेकर ग्राहकों तक जरूरी उत्पादों की सरल और सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

फ्लिपकार्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, 'देश भर में हमारे विक्रेता साझेदारों से ग्राहकों तक ग्रॉसरी और जरूरी सामान की आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जमीनी समर्थन जुटा रहे हैं। हम आपूर्ति श्रृंखला और डिलिवरी कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने के अलावा नई नियुक्ति भी कर रहे हैं।'

टीमलीज के वडेरा को ऐसी और साझेदारी सामने आने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, 'शहरी क्षेत्र में गिग कर्मचारी ज्यादातर प्रवासी हैं। देशबंदी के कारण बहुत से ऐसे कर्मचारी अपने घर लौट चुके हैं और बहुत जाना चाहते हैं। देशबंदी समाप्त होने के बाद उनमें से कितने कर्मचारी वापस लौटेंगे इसको लेकर ये कंपनियां दुविधा में हैं।'

यह रुझान गिग कर्मचारियों के बढ़ते महत्व को दिखाता है जो महामारी के समय पर लोगों को सामान कीआपूर्ति करने के लिए बहुत जोखिम उठा रहे हैं।

सॉफ्टवेयर उद्योग संगठन नैसकॉम की अध्यक्ष देवयानी घोष ने कहा, 'गिग अर्थव्यवस्था और घर से काम कर रहे लोग मुख्यधारा में काम करने वाले लोगों की तरह काफी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।'

पिछले कुछ वर्षों में गिग अर्थव्यवस्था या तकनीकी प्लेटफॉर्म की ओर से मुहैया कराए जा रहे ऐसे काम में लगे लोग, जहां पर कर्मचारी संगठन से बंधा नहीं होता है और वह मनचाही कार्य अवधि के लिए काम के घंटे का चुनाव कर सकता है, तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहां तक कि परंपरागत क्षेत्र भी अब अपने ग्राहको तक जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए अभिनव तरीके को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

रोजमर्रा के सामान (एफएमसीजी) बनाने की दिग्गज कंपनी आईटीसी ने जुबिलैंट फूडवर्क्स के साथ हिस्सेदारी की है जो भारत में डोमिनोज ब्रांड की मास्टर फ्रैंचाइजी है। मुंबई स्थित मरिको ने खाद्य तकनीक प्लेटफॉर्मों पर सफोला स्टोर शुरू करने के लिए स्विगी और जोमैटो के साथ साझेदारी की है।

आईटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इस महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने प्रयासों को फिर से दोगुना कर दिया है और अग्रिम पंक्ति के योद्धा उपभोक्ताओं तक जरूरी उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।'

इस बार की नई साझेदारियों में उल्लेखनीय अंतर यह आया है कि गिग कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।

वडेरा ने कहा कुछ गिग नियोक्ता कर्मचारियों को अपोलो हॉस्पिटल्स आदि की ओर से चलाए जा रहे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए भेज रहे हैं जहां उन्हें सुरक्षा और देखभाल के बारे में पढ़ाया जाता है।

बदलते रुझान

- इनवेस्ट इंडिया के मुताबिक जनवरी 2020 में गिग अर्थव्यवस्था का कुल आकार 3.4 अरब डॉलर था
- अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत लचीली कर्मचारी व्यवस्था के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश है
- उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो भारत में गिग कर्मचारियों के बड़े नियोक्ताओं में शुमार हैं
- जोमैटो और ओयो अपोलो हॉस्पिटल्स की मदद करे रहे हैं, पेटीएम मेडिक्स को मैक्डॉनल्ड्स फूड की डिलिवरी कर रही है
- पिछले हफ्ते स्टार्टअप, परंपरागत कारोबारों और अस्पतालों के बीच कई असामान्य साझेदारियों की घोषणा की गई और ऐसे ही कई और साझेदारी जल्द होने वाली है

केंद्र ने 13 राज्यों को दी दलहन खरीद की मंजूरी

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 6 अप्रैल

केंद्र सरकार ने 13 राज्यों को चने और मसूर की तुरंत खरीद करने के लिए लिखित मंजूरी दी है। ये दोनों बड़ी दाल रबी सीजन में उगाए जाते हैं। केंद्र ने दोनों दलहन की करीब 2,58,000 टन खरीद करने के लिए 1,250 करोड़ रुपये की भी तुरंत मंजूरी दी है।

इन 13 राज्यों को खरीद शुरू करने से पहले केंद्र से किसी तरह की औपचारिक मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य तत्काल प्रभाव से उत्पादन के 25 फीसदी तक की खरीद शुरू कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अपने प्रस्ताव पर केंद्र से मिलने वाली औपचारिक मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। खरीद पीएम-आशा सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत की जाएगी। कीमत समर्थन योजना (पीएसएस) भी पीएम-आशा का ही हिस्सा है।

कुल रबी चना उत्पादन का सरकारी अनुमान 2019-20 में 1.128 करोड़ टन का है वहीं मसूर का उत्पादन 13.9 लाख रहने का अनुमान है जिसकी 25 फीसदी तक की खरीद करने में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार सहायता करेगी।

ये 13 राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। लेकिन चना और मसूर के सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस सूची से बाहर रखा गया है। चने की खरीद के लिए राजस्थान और हरियाणा के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। राज्यों को केंद्र से औपचारिक मंजूरी मिलने का इंतजार किए बिना ही किसानों से सरसों की खरीद करने की भी अनुमति दी गई है।

- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस सूची से रखा है बाहर
- राज्य तुरंत उत्पादन के 25 फीसदी तक की खरीद कर सकते हैं

बीएस सूडोकू 3708

परिणाम संख्या 3607

			7		3		9	
7			5	1		6		
				4	9			
	2		6		5			
3		6			1			
8	7			3				9
		8	9					6
4	3							
							5	2

5	4	8	7	2	3	1	6	9
7	6	9	5	1	8	2	3	4
1	2	3	4	6	9	5	7	8
2	7	1	3	8	6	9	4	5
6	9	4	1	5	7	3	8	2
3	8	5	9	4	2	6	1	7
8	3	2	6	7	5	4	9	1
4	5	6	8	9	1	7	2	3
9	1	7	2	3	4	8	5	6

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल ★★★★☆

कोविड उपचार के लिए मानक दरें चाहते हैं बीमाकर्ता

सुब्रत पांडा और सोहिनी दास
मुंबई, 6 अप्रैल

कोविड-19 के मरीज आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता इसके उपचार की लागत का मानकीकरण चाहते हैं, जैसा जांच के मामले में किया गया है।

वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों का दावा है कि इसके उपचार के प्रोटोकॉल की लागत तय करना असंभव है, क्योंकि इस मामले में अलग उपचार की जरूरत है जो व्यक्ति की बीमारी के स्तर पर निर्भर होता है। बहरहाल निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के पास कोविड-19 के उपचार के दावे बहुत मामूली हैं। बीमकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के दावे अभी कम हैं। हरियाणा ने पहले ही संकेत दे दिया है कि आयुष्मान भारत की दरों का पालन कोविड-19 के मरीजों के उपचार में निजी अस्पतालों को करना होगा। सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी आम मरीजों के उपचार के लिए दरों को लेकर परामर्श जारी करने पर विचार किया जा रहा है। कोविड-19 की जांच की लागत प्रति जांच 4,500 रुपये सरकार ने तय किया है।

बहरहाल अस्पताल इसे व्यावहारिक नहीं मानते। कर्नाटक के एक हॉस्पिटल चेन के पदाधिकारी ने कहा, 'इसमें बचाव की लागत ही बहुत ज्यादा होगी। अगर हम अपने स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा से समझौता करते हैं तो यह मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते।' कर्नाटक में सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज चल रहा है। अगर कोई निजी अस्पताल में जाता है तो उसे सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया गिलबिले ने कोविड के 3 पुष्ट मामलों को देखा है, उनका कहा है कि औसतन इलाज पर 2 लाख रुपये खर्च आ रहा है।

उन्होंने कहा, 'अभी इसके उपचार की लागत खुली हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जांच की तरह इसके उपचार की लागत तय करने पर भी विचार किया जाएगा।'

सोमवार को चेन्नई के स्टैनली मेडिकल हॉस्पिटल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में इंटरैक्टिव रोबोट 'जैफी' के डेमो में हिस्सा लेते स्वास्थ्यकर्मी। तिरुचि के इंजीनियरों ने दो रोबोट जैफी और जैफी मेड तैयार किया है, जिससे इलाज के दौरान चिकित्सकों को संक्रमण से बचाया जा सके। *फोटो-पीटीआई*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 40

देर आए, दुरुस्त आए

यह सुकूनदेह खबर है कि केंद्र सरकार नोवेल कोरोनावायरस के खिलाफ अपनी जंग तेज कर रही है। अभी हाल तक देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कई कमियों से जूझ रही थी। बहुत कम लोगों की जांच हो रही थी, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पीपीई मसलन मास्क आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और संक्रमण के कारण निमोनिया हो जाने पर काम आने वाले वेंटिलेटर भी बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध थे। सरकार के अनुसार उसने हाल के दिनों में इन कमियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर की तैयारी पहले कर ली जानी चाहिए थी लेकिन देर से ही सही अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। आशंका यह है कि यह वायरस निकट भविष्य में नदारद होता नहीं दिख रहा है। पुराने वायरसों के उलट यह कई महीनों तक हवा में रह सकता है और इसके चलते बार-बार संक्रमण हो सकता है।

जांच प्रक्रिया अभी भी धीमी है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो जांच की जा रही है उसकी पूरी जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में दी जा रही है अथवा नहीं लेकिन यह तय है कि जांच की तादाद बढ़ी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार रविवार रात नौ बजे तक कुल 90,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके थे। अब रोजाना 9,000 जांच हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसे 20,000 प्रतिदिन किया जाएगा। हालांकि यह अभी भी जरूरी स्तर से कम होगा लेकिन सुधार साफ नजर आ रहा है। जितने ज्यादा आंकड़े होंगे, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि इससे सरकार को इस महामारी को थामने और जरूरी नीतिगत कदम उठाने में मदद मिलेगी। चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता है लेकिन इस मोर्चे पर भी सरकार सक्रिय है। खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में सरकार को 2.7 करोड़ एन 95 मास्क, 1.5 करोड़ पीपीई और 16 लाख जांच किट की आवश्यकता होगी। देश में 16,000 वेंटिलेटर हैं और 34,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से कुछ उपकरण विदेश से खरीदने होंगे। सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह पर्याप्त मात्रा में ये उपकरण जुटा ले। सरकार संक्रमण की स्थिति से अवगत दिख रही है। यदि यूरोप के उदाहरण से सबक लिया जाए तो हमारा देश उस विस्फोटक वृद्धि के मुहाने पर है जब हर चौथे या पांचवें दिन मामले दोगुना होना शुरू हो गए। यदि अगले कुछ सप्ताह में देश में 50,000 मामले हो जाते हैं तो मौजूदा लॉकडाउन को खत्म करना मुश्किल भरा निर्णय हो जाएगा। पूरी तरह सामान्य हालत में लौटना भी आसान नहीं होगा क्योंकि उससे दबी वृद्धि के उभरने और एक बार फिर इसमें तीव्र इजाफे की आशंका पैदा हो जाएगी।

सरकार को कम प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन में चरणबद्ध छूट के साथ-साथ लोगों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करना होगा।

यदि 15 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हवाई यात्रा आरंभ होती है तो विमान पर सवार होने से पहले सभी यात्रियों का परीक्षण किया जाना चाहिए, बीच वाली सीट खाली छोड़ दी जानी चाहिए या फिर हर एक सीट के बाद एक सीट खाली रखी जानी चाहिए। कंपनियों से कहा जाना चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों से यथासंभव घर से काम कराना जारी रखें। बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाए और समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। गैर जरूरी चीजों की दुकानों को सप्ताह में एक या दो दिन ही खोला जाए। इसके साथ सरकार जनता में वायरस के खतरों को लेकर प्रभावी संदेश देना जारी रखे। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को भी अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए।

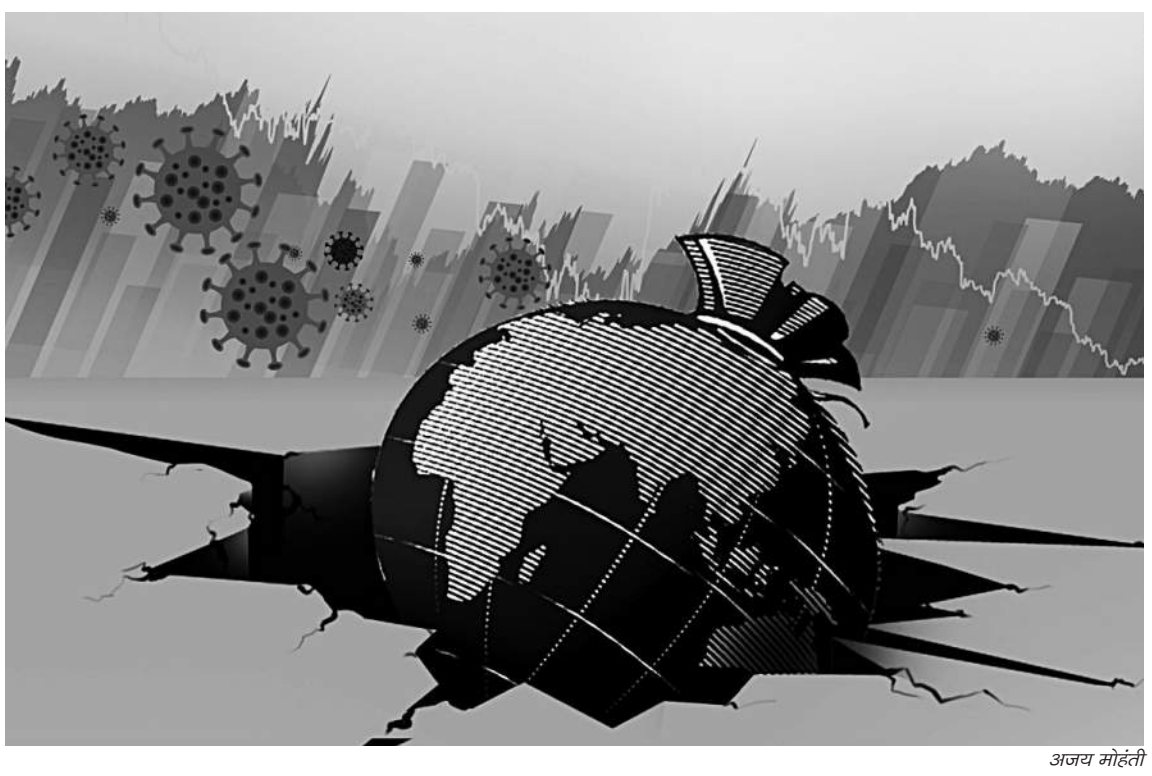

अजय मोहंती

समझदारी भरे हों नीतिगत हस्तक्षेप

कोविड-19 से निपटने के क्रम में समझदारी भरे नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अस्थायी रूप से ऐसे सुरक्षा इंतजाम करने होंगे जो बाद में संतुलन और विसंगति न छोड़ जाएं। बता रहे हैं **साजिद जेड चिनॉय**

हर गुजरते दिन के साथ दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहली, आक्रामक नियंत्रण उपाय अपनाकर हम कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोक सकते हैं। बड़ी आबादी के लॉकडाउन से निपटने के लिए आय समर्थन जरूरी है, खासकर उभरते बाजारों में जहां सुरक्षा ढांचा अधूरा और खामी भरा है। दूसरा, अचानक आर्थिक गतिविधियां ठप होने का असर अनुमान से ज्यादा भीषण होगा। सन 2020 की पहली दो तिमाहियों में विश्व अर्थव्यवस्था क्रमश: 15 और 7 फीसदी सिकुड़ेगी। यह वैश्विक वित्तीय संकट का दोगुना है। उस लिहाज से देखें तो मंदी की गहराई और उसकी अवधि न केवल इस झटके के आकार पर निर्भर होगी बल्कि इस पर भी कि क्या नीतिगत कदम ऋण और श्रम बाजारों पर असर को न्यूनतम कर सकते हैं।

यही कारण है कि विकसित देशों के नीति निर्माता खासतौर पर प्रोत्साहन पैकेज दे रहे हैं। अमेरिका ने अपने जीडीपी के 10 फीसदी के बराबर का पैकेज दिया है जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। फेडरल रिजर्व व्यापक अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए सामने आया है। वह एसएमई को सीधे ऋण दे रहा है और कॉर्पोरेट प्रतिभूति खरीद रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस में जीडीपी के 15 फीसदी के बराबर ऋण गारंटी दी गई है।

विकासशील देशों ने भी इन मुल्कों का अनुसरण किया है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये देश कम आय वाले और कमतर सामाजिक सुरक्षा वाले हैं। लॉकडाउन से जिंदगियां बच सकती हैं लेकिन लोगों की आजीविका बचाने का काम नीतिगत स्तर पर करना होगा। यही कारण है कि इन बाजारों में भी तमाम पैकेज सामने आए।

भारत ने अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया हाल ही में घोषित की। सबसे पहले ऐसी घोषणाएं की गईं जो देश के असंगठित और कामगार वर्ग के लोगों को 21 दिन के लॉकडाउन से राहत दिला सकें। बंदी की अवधि और उसके आर्थिक असर को देखते हुए ज्यादा मदद की जरूरत पड़ सकती है।

फेड की तरह आरबीआई ने भी घोषणाएं कीं। पहले उसने रीपो दर 75 आधार अंक कम की लेकिन प्रभावी दर करीब 100 आधार अंक कम हुई। दूसरा, विभिन्न ब्याज और पूंजीगत ऋण को तीन महीने के लिए स्थगित करने की इजाजत दी गई। तीसरा, ऋण विस्तार को देखते हुए आरबीआई बैंकों को टर्म लिक्विडिटी यानी टीएलटीआरओ मुहैया कराएगा ताकि वे निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकें। ये उपाय प्रोत्साहन के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता मुहैया कराएंगे।

परंतु यदि आर्थिक झटका ज्यादा गहरा हुआ तो और अधिक कदम उठाने होंगे। एसएमई को फिलहाल राहत मिल गई है लेकिन राजस्व की कमी और कंपनियों को वेतन भत्ते चुकाने की जरूरत को देखते हुए उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ सकती है। परंतु चूंकि एसएमई सबसे अधिक जोखिम में हैं इसलिए बैंक शायद उन्हें ऋण देने में अनिच्छुक हों। ऐसे में अस्थायी, आंशिक ऋण गारंटी इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बरकरार रखेगी। नीति निर्माताओं को भी नीचे तक नकदी मुहैया कराने के मामले में सकारात्मक होना पड़ेगा। कुल मिलाकर कम आय वाले परिवारों को ज्यादा नीतिगत मदद की जरूरत होगी। एसएमई और एनबीएफसी को उन्हें इन झटकों से बचाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय क्षेत्र में तनाव न बढ़े।

यह सूची बनाना आसान है कि राज्य और क्या कर सकता है या उसे और क्या करना चाहिए। परंतु उभरते बाजारों में जहां राजकोषीय गुंजाइश सीमित है और मुद्रा को सीमित लाभ है, वहां नीतिगत बाधाएं ज्यादा हैं। ऐसे में संकट समाप्त करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। लेखक जेपी मॉर्गन में चीफ इंडिया इकॉनोमिस्ट हैं। लेख में विचार निजी हैं।

यदि ऐसा नहीं हुआ तो विसंगति बढ़ेगी। 2008 को याद कीजिए। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वैश्विक मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण इतना खोखला था कि प्रतिफल की तलाश में बैंकिंग तंत्र के बाहर भारी भरकम नकदी एकत्रित हो गई। उसके चलते भारी पैमाने पर बिकवाली को बढ़ावा मिला। वित्तीय हालात तंग हुए और संकट को लेकर पेश की गई नीतिगत प्रतिक्रिया आंशिक रूप से निष्प्रभावी साबित हुई। भारत में भी 2008 के बाद का वैश्विक वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन शायद उस वक्त आवश्यक रहा हो लेकिन वर्षों बाद उसे वापस लिए जाने ने 2013 में भारत को संकट में डाल दिया था। हमें वे सबक भूलने नहीं चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोविड-19 का संकट श्रम और ऋण बाजार के जरिये बढ़े नहीं। सरकारी हस्तक्षेप ऐसे तैयार किए जाएं कि आम परिवार, छोटे कारोबार और वित्तीय बाजार को इस झटके से उबारा जा सके। इस दौरान किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

आवंटन में किफायत की बात करें तो संभव है कि कुछ छोटे कारोबार, महामारी के बाद के आने वाले दिनों में व्यवहार्य न रह जाएं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी अवसर तैयार किए जाने चाहिए। कुछ रचनात्मक विनाश और संसाधनों का पुनर्आवंटन अपरिहार्य है। नीति ऐसी होनी चाहिए जो संकट के दौरान और उसके तत्काल बाद राहत प्रदान करे। इस दौरान उसे संसाधनों के पुनर्आवंटन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी न किसी मोड़ पर ऐसा करना अनिवार्य होगा।

असंतुलन को रोकना भी समान महत्त्व की बात है। विकसित देशों में ब्याज दरें शून्य के आसपास हैं, तो कोविड-19 के कारण वित्तीय घाटा बढ़ने पर भी ऋण की स्थिरता खतरे में नहीं पड़ेगी। इसकी शुरुआत कई उभरते बाजारों से एकदम अलग होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक घाटे, उच्च ब्याज दर और काफी कम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के साथ ऋण का स्थायित्व समस्या बन सकती है अगर घाटे में इजाफा होता है। भले ही केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड की खरीदारी जारी रखें।

कई उभरते देशों में बिना भेदभाव का राजकोषीय व्यय निजी मांग में ठहराव से हो रहे नुकसान की सतत भरपाई नहीं कर पाएगा। खासतौर पर तब जबकि ये अर्थव्यवस्थाएं तमाम एसएमई के बंद होने से आपूर्ति के नकारात्मक झटके से दो चार हों। नकारात्मक आपूर्ति झटके से निपटने के लिए सकारात्मक मांग भर से काम नहीं चलता।

इन बातों का यह अर्थ नहीं कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति को कोविड-19 के आर्थिक झटके से बचाने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। परंतु इतिहास बार-बार बताता है कि नीतिगत प्रोत्साहन डालना, निकासी से ज्यादा आसान है। उभरते बाजारों में नीतिगत हस्तक्षेप समझदारी से आजमाया जाना चाहिए ताकि संकट के दौर में अस्थायी लेकिन गहरा सुरक्षा ढांचा तैयार हो सके और बाद में कोई विसंगति और असंतुलन भी नहीं पैदा हो। मौजूदा माहौल के दबाव में आने वाले दिनों को नहीं भूलना चाहिए।

(लेखक जेपी मॉर्गन में चीफ इंडिया इकॉनमिस्ट हैं। लेख में विचार निजी हैं।)

कोरोना की दुनिया में एकदूसरे पर निर्भरता

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मैं लॉकडाउन के समय यह लेख लिख रही हूं। भारत कोरोनावायरस के तीसरे और सामुदायिक प्रसार के सबसे भयावह दौर के मुहाने पर है और सरकार ने लोगों से सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद करने और सामाजिक दूरी बनाने का आह्वान किया है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। कम से कम मेरी याददाश्त में इससे पहले कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब कोई छोटी चीज इतनी तेजी से बेकाबू हो गई और उसने दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया।

जनवरी में ही हमें पहली बार नोवेल वायरस के बारे में वास्तविक खबर मिली थी जो जानवरों से इंसान में आया था और चीन में लोगों की जान ले रहा था। हमने ऐसी तस्वीरें देखीं जिनमें लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद किया जा रहा था, लाखों कारोबारों और घरों को बंद कर दिया गया, रातोरात अस्पताल बनाए गए और ऐसा लगता था कि इसे काबू में कर लिया जाएगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए झटका था लेकिन उम्मीद थी कि चीन इससे उबर जाएगा। चीजें सामान्य ढंग से चल रही थी। लेकिन तभी इस वायरस ने जल्दी ही अपने नए ठिकाने ढूंढ लिए -इटली और ईरान। इटली में चीजें पूरी तरह बेकाबू हो गई हैं और ईरान में इसने विकराल रूप ले लिया है। अब यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। यह पूरी तरह अविश्वसनीय लगता है।

जब मैं यह लेख लिख रही हूं तो भारत में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है जिनमें से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में यह संख्या बेहद मामूली है। इटली में करीब 125,000 मामले हैं और न्यूयॉर्क में 113,700 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और हर छह दिन में इनकी संख्या दोगुनी हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है लेकिन सीमित जांच के कारण वे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहीं असली सवाल उठता है। भारत जैसे देशों को क्या करना चाहिए जहां जांच की सीमित सुविधाएं हैं और जन स्वास्थ्य से जुड़ा बुनियादी ढांचा इससे भी ज्यादा सीमित है? सभी तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि जब इसका सामुदायिक प्रसार होगा तो मरने वालों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये देश मरीजों को गहन इलाज मुहैया नहीं करा सकते हैं।

यही वजह है कि भारतीयों के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसे शुरुआत में ही काबू किया जाए और फैलने से रोका जाए। हम इसके सामुदायिक प्रसार से निपटने में सक्षम नहीं हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें अपनी जांच क्षमताओं को बढ़ाना होगा लेकिन यह भी तय है कि अगर इसका सामुदायिक प्रसार हुआ तो हम कभी भी पर्याप्त संख्या में जांच नहीं कर पाएंगे। इसलिए संक्रमित लोगों की पहचान और उन्हें अलग-थलग करने के लिए जांच होनी चाहिए।

हमें यह समझना चाहिए कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है ताकि भारत में दूसरे देशों की तरह इसका सामुदायिक प्रसार न हो। यह इतनी तेजी से फैलता है कि कई देशों में तो इसने कुछ ही दिनों में पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। इस वायरस के लिए कोई बंधन नहीं है लेकिन इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि इसके प्रसार की श्रृंखला को तोड़ दिया जाए। हालांकि ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम जाएगी। यह खासकर गरीबों और अपना काम करने वालों की आजीविका को बरबाद कर देता है। सरकारों को ऐसे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए ताकि वे इस अप्रत्याशित वैश्विक आपदा से निपट सकें।

लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए यह कुछ बुनियादी चीजों के बारे में सोचने का समय है। इनमें से एक मुद्दा वैश्विक सहयोग का है। किसी महामारी के लिए दुनिया पर कहर ढाने का यह सबसे अच्छा समय है लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि यह सबसे बुरा समय है। दुनिया में इस समय ऐसा कोई सम्मानित दूरदर्शी नेता या संस्था नहीं है जो हमें ऐसी आपदा से बाहर निकाल सके जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। पिछले कुछ महीनों में हमने जो कुछ देखा है वह स्वार्थ और आत्म-संरक्षण की शर्मनाक पराकाष्ठा है।

जलवायु परिवर्तन जैसे एक और अस्तित्वगत खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत करने वाले हम जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह खबर नहीं होनी चाहिए। कोरोनावायरस ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को घुटनों पर ला दिया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने विकराल संकट से निपटने के लिए दुनिया के देशों के बीच वैश्विक सहयोग के लिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों? इसे काबू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? आने वाले हफ्तों में मैं इस पर और चर्चा करूंगी।

फिर जन स्वास्थ्य का भी मामला है। कोरोनावायरस हमें सिखाता है कि हम अपनी कमजोर कड़ी के बराबर मजबूत हैं। अगर हर किसी की जन स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच नहीं होगी या अगर जन स्वास्थ्य सेवा कमजोर होगी तो हम इस महामारी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अधिकांश उभरते देशों और यहां तक कि अमेरिका में भी निजी स्वास्थ्य सेवा का यही हाल है। साथ ही देशों के भीतर क्षमता का निर्माण भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि अगर किसी देश का कोई इलाका कमजोर हुआ या दुनिया का कोई देश कमजोर हुआ तो यह महामारी वहां पैर पसारेगी और फिर वहां से फैलेगी। कितने लंबे समय तक हम अपनी सीमाओं को बंद रख पाएंगे? यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। इससे मेरा तीसरा सवाल पैदा होता है जो कोरोना के बाद वैश्वीकरण की प्रकृति के बारे में है। क्या हम अपनी व्यवस्थाओं की कमजोरी से सीखेंगे और वैश्विक भागीदारी के जरिये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में निवेश कर उन्हें मजबूत बनाएंगे? आइए इस मुश्किल दौर में इस पर चर्चा करते रहें।

कानाफूसी

प्रचार से छवि सुधार

देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद अलग-अलग इलाकों से पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की कई खबरें सुनने को मिली हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन वहां से ऐसी कई रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन परेशान हो गया। आखिरकार इसका तोड़ निकाल लिया गया। पुलिस विभाग ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और अपनी छवि सुधारने का निर्णय किया है। इस क्रम में भोपाल पुलिस ने एक दिलचस्प कदम उठाया है। विभाग एक गीत के माध्यम से लोगों को कोरोनावायरस के खतरे और इससे बचाव के बारे में जानकारियां दे रहा है। इसके लिए स्थानीय डीजे संचालकों की मदद ली गई है और शहर की गली मोहल्ले में इस गीत को लगातार बजाया जा रहा है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दो-दो डीजे इस काम के लिए लगाए गए हैं।

सत्ता संघर्ष

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए चिंतित करने वाली खबर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टी एस सिंहदेव के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिल रहा है। दरअसल 67 वर्षीय सिंहदेव को लगता है कि दिसंबर 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद उन्हें राज्य का मुखिया बनाया जाना चाहिए था। चूंकि लोकसभा चुनाव करीब थे और कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाना चाहती थी इसलिए उसने बघेल को इस पद पर नियुक्त किया। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि इस बात पर सहमति बनी थी कि ढाई वर्ष तक बघेल इस पद पर रहेंगे और बाकी का कार्यकाल सिंहदेव के पास रहेगा। अब सिंहदेव के खेमे का कहना है कि बघेल जोरशोर से जनसंपर्क कायम कर रहे हैं और सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद कोविड-19 से जुड़े तमाम निर्णय वह स्वयं ले रहे हैं। सिंहदेव के एक करीबी विधायक पर पिछले दिनों प्रदेश की पुलिस ने उस समय कार्रवाई कर दी थी जब वह राहत सामग्री बांटने बाहर निकले थे। बघेल और सिंहदेव के बीच कुछ निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के निर्णय को लेकर भी बहुत अधिक असहमति थी। बाद में इस निर्णय को बदल दिया गया।

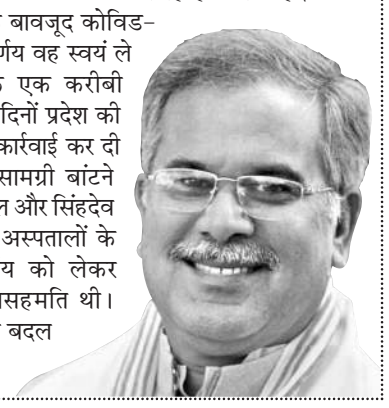

आपका पक्ष

कोरोना के खिलाफ लोगों का योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से पूरे भारत में 21 दिन तक की लॉकडाउन की घोषणा की। इसके बाद चंडीगढ़ की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने निश्चय किया कि कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए। लोगों की सतर्कता और समझदारी के साथ-साथ बच्चों ने भी इस लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और दूसरों को भी अपने से एक मीटर की दूरी रखने के लिए सचेत किया। भले ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा लेकिन 21 दिन का परिवार का एक साथ होना और मिलजुल कर समय व्यतीत करना शायद दोबारा आए। इसी दौरान दूरदर्शन में प्रस्तुत होने वाले धारावाहिक कार्यक्रम रामायण, रंगोली, महाभारत जैसे पौराणिक नाटक फिर से शुरू किए गए। लोगों की दिनचर्या बदल गई। बहरहाल कोरोना को खत्म करने के लिए सभी लोगों का अपना योगदान देना जरूरी है।

दिवाकर, खंडवा

राष्ट्रप्रेम की मिसाल पेश करते वर्दीधारक

प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल रात 9 बजे घरों की लाइटें बंद कर मोमबत्ती दीये जलाने की अपील की थी

आज पूरा विश्व कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रहा है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में लोग अपने घरों में हैं। हर कोई इस आपदा के अंजाम इतने सहमा हैं कि घर से निकलना तो दूर छींकने-खांसने से भी कतराने लगे हैं। जो घर वर्षों से वीरान पड़े थे आज वह भी गुलजार हो रहे हैं। आज हर व्यक्ति इंसानियत के नाते राष्ट्रधर्म का निर्वहन करने में लगी है। इसमें पुलिस व डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी व मानवधर्म का पालन करते हुए सेवा में लगे हैं। ऐसे लोग जो वर्दीधारी को गैर जिम्मेदार समझते थे आज उन्हें भी इन वर्दीधारियों का महत्त्व पता चल गया है। वर्दीधारी खून पसीना एक करके जनसेवा में दिन-रात लगे हैं। इन वर्दीधारियों के लिए पूरा राष्ट्र ही इस विपदा में अपना परिवार है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ईमानदारी से मानवसेवा कर रहा है। आज इस विकट घड़ी में इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है।

भैरु सिंह राठौड़, जोधपुर

महिलाओं को मिले सम्मान

आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में खड़ी हैं। शिक्षा और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि भी हुई है। हाल में निर्भया के दोषियों के फांसी के बाद उनके वकील की निर्भया मामले में टिप्पणी, राजनेताओं द्वारा कई बार महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी अभी भी पुरुषवादी सोच को उजागर करती है। आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और उन्हें सेना, नौसेना में कमांड का अधिकार मिल चुका है। इसके अलावा इसरो-नासा जैसी जगहों पर महिलाएं अपना लोहा मनवा रहीं हैं। वहां ऐसी परिस्थितियों का आना दिया तले अंधेरा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2018 में लगभग 91 रोजाना बलात्कार के तथा लगभग 15 लाख से ज्यादा मामले 2018 में पूरे वर्ष महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के सामने आए। वहीं 7 वर्ष बाद निर्भया को मिला न्याय वैसे भी अधूरा है जबकि कठुआ, हैदराबाद जैसे दर्दनाक कृत्य लगातार सामने आ रहे हों। बहरहाल सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही है लिहाजा उम्मीद के लिए यह कदम सराहनीय है लेकिन बिना सख्ती ऐसे अपराधों को खत्म करना मुमकिन नहीं लगता।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोना के क्लेश में ठीक से संभालें अपना निवेश

कोविड-19 के गहराते संकट का असर अर्थव्यवस्था पर कई महीनों तक दिखने का अंदेशा है। ऐसी स्थिति में धन और निवेश के संग समझदारी बरतनी होगी

बिंदिशा सारंग

जरा सोचिए कि कितनी उथलपुथल मची हुई है – कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह लुढ़क चुके हैं, उद्योग ठप होते जा रहे हैं और तमाम देश अपने यहां लॉकडाउन यानी बंदी का ऐलान करते जा रहे हैं। महीना भर भी नहीं गुजरा है और भारत के लोग खुद को ऐसे वैश्विक बवंडर में फंसा महसूस कर रहे हैं, जिसने हर किसी की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। विमानन जैसे कुछ क्षेत्र पहले ही वेतन में कटौती शुरू कर चुके हैं और कुछ अरसे बाद ही हमें पता चलेगा कि इस बवंडर की वजह से कितने बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है। ऐसे वक्त में हर परिवार इसी उधेड़बुन में लगा है कि पैसा कैसे संभाला जाए और जरूरी सामान घर में किस तरह आए। मगर दिक्कत यह है कि इसका जो तरीका किसी एक परिवार के लिए कारगर होगा, वह दूसरे परिवार के साथ नहीं चल पाएगा। इसीलिए परिवारों या लोगों को चार श्रेणियों में बांटकर उनके लिए पैसा संभालने के गुर देना बेहतर रहेगा।

हाल की गिरावट से इक्विटी में कम हुआ मुनाफा

योजनाएं	औसत प्रतिफल (1 साल) फीसदी में	औसत प्रतिफल (5 साल) फीसदी में
आवर्ती जमा*	5.40-7.25	6.5-8.42
सावधि जमा*	6.30-8.25	6.25-9.00
लिक्विड फंड	5.70	6.87
डेट फंड (मसलन कॉरपोरेट बॉन्ड फंड)	5.19	6.95
हाइब्रिड फंड	-22.60	0.47
इक्विटी फंड (लार्ज कैप)	-29.49	-0.74

म्युचुअल फंडः पांच साल का श्रेणीवार प्रतिफल, *सभी सरकारी, निजी और स्मॉल सेविंग बैंक, स्रोतः टीबीएनजी कैपिटल एडवाइजर्स, वेबसाइट और वैल्यू रिसर्च

आपातकालीन कोष

यदि आपने अचानक आने वाली आफत के लिए रकम का इंतजाम पहले ही कर रखा है और आपका निवेश भी ठीकठाक है तो आपको माली दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास तीन से छह महीने तक घर चलाने के लिए जरूरी रकम जमा है, उसने अच्छी तरह निवेश किया है और उस पर ज्यादा कर्ज भी नहीं है तो उसे आराम से बैठना चाहिए। एएसके वेल्थ एडवाइजर्स में मैनेजिंग पार्टनर और फैमिली ऑफिस प्रमुख निशांत अग्रवाल मानते हैं, 'ऐसे लोगों के लिए हालात कुछ ज्यादा सहूलियत भरे होंगे। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट के बाद भी निवेशकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तस्वीर और साफ नहीं हो जाती एक फंड छोड़कर दूसरे फंड में जाने की अपनी इच्छा दबाकर रखिए।' अगर बुरी खबरों का सिलसिला जारी रहता है तो हो सकता है कि एक बार फिर बाजार लुढ़कने जा रहा हो। लेकिन यह भी सच है कि आगे जाकर बाजार फिर उछाल भरेगा। इसीलिए इस वक्त हाथ पर हाथ धरकर बैठने में ही समझदारी है।

अगर आपने इक्विटी में पर्याप्त निवेश नहीं किया है और आपके हाथ में नकदी पड़ी है तो निवेश करने का यही सबसे उम्दा वक्त है। अग्रवाल समझाते हैं, 'अपनी किस्मत को सराहिए कि इस तरह का मौका आपके हाथ लगा है। आप इंडेक्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्युचुअल फंड अथवा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के जरिये लार्ज कैप शेयर खरीद सकते हैं। आप अपनी नकदी में से 5 से 8 फीसदी रकम लगा सकते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे पूरी रकम इसमें लगाई जा सकती है।'

अगर आपने इक्विटी यानी शेयरों में रकम लगा रही है तो भी आप अगले तीन महीने तक अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। इनक्रेड वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य कार्य अधिकारी नितिन राव की सलाह है, 'इक्विटी आवंटन के लिए हम सक्रिय प्रबंधन वाले फंडों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों को तरजीह देंगे। कम जोखिम चाहने वाले निवेशक इंडेक्स फंड या इंडेक्स ईटीएफ चुन सकते हैं। डेट निवेशक भी अपने डेट प्रतिफल को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए एएए रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। संपत्ति आवंटन पर दोबारा नजर डालना भी इस दौरान ठीक रहेगा।'

निवेश है मगर कोष नहीं

आज की तारीख में सबसे जरूरी कुछ है तो वह है आपात स्थितियों के लिए बचाकर रखी गई रकम। मगर इससे भी जरूरी यह सवाल है कि यह रकम जमा किस तरह की जाए? इसके लिए आपके पास तमाम विकल्प हैं – इक्विटी या इक्विटी म्युचुअल फंड को छोड़कर लिक्विड फंड का दामन थाम लीजिए या बैंक में पड़ी जमा रकम निकाल लीजिए। लैडरअप वेल्थ मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक राघवेंद्र नाथ कहते हैं, 'चूंकि इस श्रेणी के लोगों के पास आपात स्थितियों के लिए रकम नहीं है और शेयरों का हाल बुरा है, इसलिए उन्हें शेयर किसी सूरत में नहीं बेचने चाहिए।'

अगर आपके पास सावधि जमा (एफडी) में या दूसरे डेट फंडों में कुछ रकम पड़ी है तो उसे इस्तेमाल कर आपात कोष तैयार करने की कोशिश करें। इतना ही नहीं सोना भी इस मामले में कारगर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय में सोना चढ़ा है तो उसे बेचकर आपात कोष तैयार करना भी बुरा विचार नहीं है। आप सोने के जेवरात आदि के बदले कर्ज ले सकते हैं और अगर आपके पास एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के रूप में सोना पड़ा है तो उसे बेचा जा सकता है।

अगर आपके पास बैंक खातों में रकम पड़ी है तो कुछ खाते बंद कर उसे एक जगह जमा करने में भी कोई बुराई नहीं है। एमबी वेल्थ सॉल्यूशन्स के संस्थापक एम बर्वे समझाते हैं, 'नौकरियां बदलने के कारण कई लोगों के ढेर सारे बैंक खाते खुल जाते हैं और कई बार उनमें से कुछ खातों में नकदी भी पड़ी रहती है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि पति-पत्नी दोनों के खाते अगर खंगाले जाएं तो कुल इतनी रकम जमा मिलेगी कि दो महीने का पूरा खर्च निकल जाएगा।' मगर इन खातों को सक्रिय करना पड़ेगा। निष्क्रिय खाते को सक्रिय बनाने के लिए आपको बैंक की शाखा तक जाना होगा।

क्या करें फ्रीलांसर

अगर आप नौकरीपेशा नहीं हैं बल्कि फ्रीलांसर या कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए हालात ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांसरों का काम घटने वाला है, इसलिए आपको फौरन हरकत में आना पड़ेगा। टीबीएनजी कैपिटल एडवाइजर्स के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी तरुण बिरानी कहते हैं, 'ऐसे लोगों को अपने पास ज्यादा नकदी रखनी चाहिए। इस समय अनिश्चितता बहुत अधिक है, इसलिए हम उन्हें कम से कम छह महीने के खर्च के लिए जरूरी नकदी अपने पास रखने का मशविरा दे रहे हैं। जरूरत पड़े तो वे जोखिम की संभावना आंककर निवेश खत्म भी कर सकते हैं।'

बिरानी कहते हैं, 'आदर्श स्थिति तो यह है कि कर्ज से एकदम बचा जाए। अगर बहुत बुरी हालत होती है और आपके पास इक्विटी में निवेश तो है मगर हाथ में नकदी बिल्कुल नहीं है तो आपको लागत के बरअक्स फायदे का विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आती है तो शेयर बेचने के बजाय छोटी अवधि के लिए कर्ज लेकर अपनी जरूरत पूरी करना बेहतर होगा।'

लॉकडाउन खत्म होने और हालात सामान्य होने के बाद भी फ्रीलांसरों को कुछ महीनों के लिए सभी गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम कसनी होगी। राव याद दिलाते हैं, 'फ्रीलांसर इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें मिलने वाला काम अर्थव्यवस्था की स्थिति के हिसाब से ही बढ़ेगा या घटेगा।'

निवेश भी ईएमआई भी

अगर आप लगातार निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आवास ऋण या दूसरे किस्म के कर्जों की मासिक किस्तों (ईएमआई) का बोझ है तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर आपका वेतन देर से आ रहा है या उसमें कटौती कर दी गई है या आपकी नौकरी ही चली गई है तो मुश्किल बहुत भारी होने जा रही है। ऐसी सूरत में नाथ का मशविरा है, 'यह मुश्किल दौर है। अपने निवेश के कुछ हिस्से को भुना लीजिए और कर्ज को वक्त से पहले चुका दीजिए ताकि आपके सिर से ईएमआई का बोझ कम हो जाए। लेकिन अगर आपकी इतनी कुव्वत है कि आप ईएमआई का बोझ बरदाश्त कर सकते हैं तो ईएमआई और निवेश दोनों को साथ ही चलाते रहना अच्छा होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले दो साल में आपके निवेश पर मिलने वाले मुनाफे की दर आपके आवास ऋण की ब्याज दर से अधिक हो जाएगी।' एक विकल्प और है। राव की तरकीब कुछ अलग है। वह कहते हैं, 'कुछ महीनों के लिए ईएमआई रोकने की दरख्वास्त बैंक से कीजिए या एफडी अथवा सिक्योरिटी के बदले ओवरड्राफ्ट ले लीजिए और कुछ समय के लिए उसी रकम से काम चलाइए।'

निवेशकों के लिए जोखिम लेने का समय यह नहीं

संजय कुमार सिंह

शेयरों में इन दिनों अनिश्चितता से खुदरा निवेशकों को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ है, लेकिन फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में गिरावट ने उन्हें बिल्कुल चौंका दिया है। पिछले सप्ताह डेट फंडों को हुए भारी नुकसान से कई निवेशकों को जबरदस्त चूना लगा है। आम तौर पर सुरक्षित समझे जाने वाले छोटी अवधि के फंडों में भी गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाओं से उन्हें जरूर राहत मिली है। रिजर्व बैंक के कदमों से पहले करीब एक पखवाड़े में बॉन्ड कमजोर हो गए थे और प्राप्तियों में खासी तेजी दिखी थी। 3 महीने से लेकर 3 वर्ष में परिपक्व होने वाले बॉन्ड पर खासा असर हुआ था। बाजार में नकदी की भारी कमी इसकी मुख्य वजह थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारी बिकवाली की थी और विषेशज्ञों की नजर में बॉन्ड की खस्ता हालत के लिए यह बात मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। फंड्स इंडिया के शोध प्रमुख अरुण कुमार कहते हैं, 'विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत सहित तेजी से उभर रहे बाजारों से रकम निकाल रहे हैं असैर इस रकम को सुरक्षित बाजारों में डाला जा रहा है। मार्च में वे भारतीय बॉन्ड बाजार से करीब 52,910 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं।'

ऐक्सिस बैंक में फिक्स्ड इनकम प्रमुख आर शिवकुमार का कहना है कि डेट एवं शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुपये में कमजोरी की प्रमुख वजह रही है। उन्होंने कहा, 'रुपये में कमजोरी से बॉन्ड पर प्राप्तियां भी बढ़ गईं। वित्त वर्ष के अंत में कंपनियों द्वारा रकम निकाले जाने, कोविड-19 की महामारी फैलने और म्युचुअल फंडों द्वारा बिकवाली किए जाने से भी बॉन्ड में कमजोरी आई।'

बाजार रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप की उम्मीद जरूर कर रहा था, लेकिन उसे इतने बड़े कदम की उम्मीद नहीं थी। सुंदरम म्युचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी द्विजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, 'बाजार रीपो दर में 50 आधार अंक की कमी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आरबीआई ने इसमें 75 आधार अंक तक की कटौती कर दी। बाजार नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में कमी की उम्मीद नहीं कर रहा था और उसे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीपो ऑपरेशंस (टीएलआरओ) की भी उम्मीद नहीं थी।'

खासकर टीएलआरओ से बॉन्ड बाजार में हालत सुधर सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि अब कारोबारियों को लग रहा है कि हालत सुधारने के उपाय मौजूद हैं और बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेकर नकदी की किल्लत दूर कर सकते हैं। आरबीआई के कदमों से प्राप्तियों में कमी आनी शुरू हो गई है। एक साल तक की अवधि के बॉन्ड में 100 से 250 आधार अंक तक की कमी आई है। इसी तरह 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड में प्राप्तियां करीब 150 अंक तक कम हो गई हैं। डेट फंडों की श्रेणी का औसत प्रतिफल भी सुधर गया है।

आरबीआई के उपायों से पहले डेट फंडों में गिरावट अल्पावधि की थी, लेकिन खुदरा निवेशकों के लिए इसे भी झेलना मुमकिन नहीं है। उन्हें खास तौर पर साख से जुड़े जोखिमों से चिंतित होने की जरूरत है। कोरोनावायरस के कारण कई कंपनियों का परिचालन लगभग ठप हो गया है, जिससे वे निकट अवधि में भुगतान में चूक कर सकती है। जाहिर है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा। कुमार कहते हैं, 'जब तक आपका निवेश उच्च रेटिंग वाले फंड में आपका निवेश है तब तक आप के लिए जोखिम कम है। जिन फंडों की अवधि 3 वर्ष तक ही है, वे निवेश के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।' वैलिडस वेल्थ के मुख्य निवेश अधिकारी राजेश चेरुवु कहते हैं, 'शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग और पीएसयू फंडों में चरणबद्ध तरीके से निवेश किया जा सकता है।' चेरुवु को लगता है कि दीर्घ अवधि के फंडों में निवेश से बचना चाहिए। बकौल श्रीवास्तव, सरकार बड़े पैमाने पर उधारी ले सकती है, जिससे बाद में दीर्घ अवधि के फंडों के साथ परेशानी पेश आ सकती है। उन्होंने कहा, 'आप उन फंडों में निवेश करने से बचें, जिनकी परिपक्वता आपकी निवेश योजना के समय से अधिक है। अगर ऐसा होता है तो पिछले महीने की तरह प्राप्तियों में तेजी आने से आपको नुकसान हो सकता है।'

कोरोना का असर

- पिछले सप्ताह डेट फंडों को हुए भारी नुकसान से कई निवेशकों को जबरदस्त चूना लगा
- सुरक्षित समझे जाने वाले छोटी अवधि के फंडों में भी गिरावट
- कोरोनावायरस के कारण कई कंपनियों का परिचालन लगभग ठप हो गया है, जिससे वे निकट अवधि में भुगतान में चूक कर सकती है

ब्याज दर पर कैंची चली मगर लघु बचत योजनाएं अब भी भली

शेयर बाजार की खस्ता हालत के बीच छोटी बचत योजनाएं ब्याज दर में कटौती के बावजूद आपके निवेश को ज्यादा महफूज रख सकती हैं

जयदीप घोष और संजय कुमार सिंह

सरकार ने पिछले हफ्ते छोटी बचत दरों की ब्याज दर में अच्छी खासी कटौती कर दी। हालांकि यह अप्रत्याशित कदम नहीं था और रीपो दर तथा नकद आरक्षी अनुपात में भारीभरकम कटौती के भारतीय रिजर्व बैंक के कदम के बाद सरकार की इस घोषणा का इंतजार ही किया जा रहा था। मगर ब्याज दर में इतनी तगड़ी कैंची चलने का अंदेशा शायद ही किसी को रहा हो। सरकार ने चालू तिमाही यानी अप्रैल से जून महीने के लिए लघु बचत दरों में 70 से 140 आधार अंकों की कटौती का ऐलान कर दिया, जो वाकई में अप्रत्याशित था।

सरकार के इस फैसले की सबसे ज्यादा मार बुजुर्गों और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में रकम लगाने वालों पर पड़ी है। अभी तक सरकारें बुजुर्गों को रियायत और प्रोत्साहन देती आई थीं मगर इस बार वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के ब्याज की दर पूरे 120 आधार अंक कम हो गई। इन योजनाओं पर 8.6 फीसदी ब्याज मिल रहा था, लेकिन अब केवल 7.4 फीसदी ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ भी 7.9 फीसदी के बजाय अब 7.1 फीसदी ब्याज ही देगा यानी उसमें भी 80 आधार अंक की कमी आ गई है। मगर सबसे ज्यादा कटौती 1 से 3 साल की सावधि जमा योजनाओं के ब्याज में की गई है। इनकी ब्याज दर 140 आधार अंक कम कर दी गई है। अछूती रही तो केवल बचत खाते पर ब्याज की दर। यह अब भी सालाना 4 फीसदी पर बरकरार है।

सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार और पर्सनलफाइनैंसप्लान डॉट इन के संस्थापक दीपेश राघव कहते हैं, 'ये दरें जानबूझकर ज्यादा रखी गई थीं। 10 साल के सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल फिलहाल 6.13 फीसदी के आसपास चल रहा है। ऐसे में पीपीएफ पर प्रतिफल की दर 7.9 फीसदी पर रखने की कोई तुक ही नहीं बनती। लघु बचत योजनाओं में ब्याज की दर ऊंची रहने का मतलब यह था कि बैंकों को भी अपनी जमा दरें ऊंची रखनी पड़तीं। ऐसे में अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर की सुविधा ठप पड़ जाती। छोटे निवेशक के लिहाज से देखें तो यह कदम नुकसानदेह है मगर व्यापक तस्वीर देखी जाए तो यह अनुचित नहीं लगता।'

बैंकबाजार के मुख्य कार्य अधिकारी आदिल शेट्टी इस झटके के बाद भी लघु बचत योजनाओं से किनारा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। उनके हिसाब से निवेश में इन योजनाओं का खास स्थान है। वह कहते हैं, 'दर में कटौती के बाद भी पीपीएफ, एनएससी, डाकघर सावधि जमा और दूसरी छोटी बचत योजनाएं निश्चित प्रतिफल देती हैं और उनमें पूंजी सुरक्षित भी रहती है। इनके जरिये हमारी निवेश की रणनीति तैयार होती है। दुनिया भर के हालात और मंदी की बढ़ती आशंका के बीच कम ब्याज दर देखकर इन योजनाओं में निवेश जारी रखने से परहेज मत कीजिए। याद रखिए कि दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से इन योजनाओं में निवेश अहम है।'

बेशक ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है मगर इनमें से कई योजनाओं पर ब्याज दर अब भी अधिक है और वे आकर्षक बनी हुई हैं। बैंक तो पहले ही जमा पर ब्याज दर में कटौती करने लगे हैं। भारतीय स्टेट बैंक रीपो दर में कटौती के बाद उधारी दरों में 75 आधार अंक की कटौती की मगर उसने खुदरा ग्राहकों के लिए जमा पर ब्याज दर में भी 20 से 50 आधार अंक की कमी कर डाली। नई परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति स्टेट बैंक की सावधि जमा में तीन महीने के लिए पैसा लगाता है तो उसे 5 फीसदी की दर से ब्याज हासिल होगा। लेकिन बैंक की एक साल की दर 5.70 फीसदी पर बरकरार है और वरिष्ठ नागरिकों को 50 आधार अंक ज्यादा यानी 6.2 फीसदी की दर से ब्याज हासिल होगा।

निवेश का प्रदर्शन देखें तो पिछले कुछ समय में डेट फंडों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। पिछले तीन महीनों में अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड श्रेणी का औसत प्रतिफल 1.26 फीसदी रहा है और इनका एक साल का प्रतिफल 0.53 फीसदी रहा है। सभी डेट फंड श्रेणियों में इस श्रेणी का औसत प्रतिफल तीन महीने में -1.37 फीसदी से 4.46 फीसदी तक रहा है। पूरे साल के लिए प्रतिफल का -2.64 फीसदी से 15.68 फीसदी तक है।

जोखिम से परहेज करने वालों को भी अपने पोर्टफोलियो में इन योजनाओं को रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि डेट फंड की श्रेणी में काफी उथलपुथल चल रही है। पिछले 18 महीनों में बड़ी संख्या में कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है, जिसकी वजह से फंड कंपनियों को ऐसी प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जिसमें फंड कंपनी किसी भी एक पोर्टफोलियो में भुनाने लायक परिसंपत्तियों को उन परिसंपत्तियों से अलग करता है, जो फंसी होती हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है। कुछ फंड कंपनियों ने अपनी अलग-अलग डेट योजनाओं में कई कंपनियों की प्रतिभूतियों का वर्गीकरण ऐसे ही करना शुरू कर दिया है और यह जोखिम लेने वालों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है।

निवेशक रकम लगाने के लिए कोई भी विकल्प चुनें मगर पहले उन्हें लघु बचत योजनाओं पर कर कटौती के बाद मिलने वाला प्रतिफल देखना चाहिए और उसकी तुलना निश्चित आमदनी वाली अन्य योजनाओं से करनी चाहिए। ऐसा करने पर पता चलेगा कि छोटी बचत योजनाओं का प्रदर्शन कितना जानदार रहा है।

राघव कहते हैं, 'सभी योजनाओं और अन्य डेट योजनाओं के प्रतिफल में भी कमी आएगी। आपको ऐसे विकल्प मिलने की संभावना नहीं है, जो आपको बेहतर प्रतिफल दर देंगे। कर मुक्त बॉन्ड भी द्वितीयक बाजार में बमुश्किल 5.5 फीसदी प्रतिफल दे पा रहे हैं, जबकि पीपीएफ खाते में निवेश कर आप अब भी 7.1 फीसदी प्रतिफल हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते पर मिलने वाली रकम पूरी तरह कर मुक्त है। यह वजह भी इन योजनाओं को आकर्षक बनाती है।'

नई दरें (अप्रैल-जून 2020 के लिए)

	फीसदी में	कमी (आधार अंक)
बचत जमा	4.0	0
1-3 साल की सावधि जमा	5.5	140
5 साल की सावधि जमा	6.7	100
5 साल की आवर्ती जमा	5.8	140
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	7.4	120
राष्ट्रीय बचत पत्र	6.8	110
किसान विकास पत्र	6.9	70
सार्वजनिक भविष्य निधि	7.1	80
सुकन्या समृद्धि खाता	7.6	80

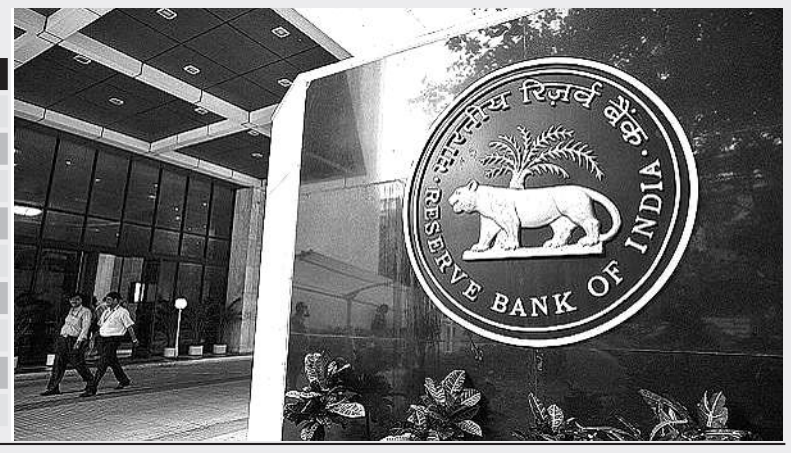

सरकार ने चालू तिमाही यानी अप्रैल से जून महीने के लिए लघु बचत दरों में 70 से 140 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की

कोरोना संकट की घड़ी में अन्नदाता की मुश्किलें

कोरोनावायरस के कारण देश में लॉकडाउन घोषणा के बाद बाजार व मंडियों में आवक कम हो गई है, किसान अपनी उपज मंडियों के बाहर फेंक रहे हैं

सोमेश झा, राजेश भयानी और संजीव मुखर्जी

रामभूल दिल्ली के बाहरी इलाके बख्तावरपुर में अपने खेत में पालक की खेती करते हैं। रोजाना वह इसे बेचने के लिए छह किलोमीटर दूर स्थित एशिया के सबसे बड़े सब्जी और फल बाजार आजादपुर मंडी पहुंचते हैं। इस तरह वह रोज टेम्पो में 12 किमी की यात्रा करते हैं। आम दिनों में वह दो घंटे में 10 क्विंटल पालक बेचते हैं और फिर अपने घर चल देते हैं। लेकिन ये सामान्य दिन नहीं हैं। अब वह मुश्किल से चार क्विंटल पालक बेच पाते हैं और खरीदारों के लिए उन्हें शाम तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद वह पैदल ही घर का रुख करते हैं। वह कहते हैं, 'एक हफ्ते में मुझे पालक की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से घटाकर छह रुपये करनी पड़ी है।' सोमवार को वह मंडी नहीं आए और उन्होंने अपनी फसल गायों को खिला दी।

तेजपाल आगरा के करीब स्थित इस्लामपुर गांव के गन्ना किसान हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने तीन बार अपनी फसल को दिल्ली और मुंबई की मंडियों में भेजने की कोशिश की, लेकिन ट्रकवाले जाने को तैयार नहीं होते। जो जाने को तैयार होते हैं, वे सामान्य से दो गुना ज्यादा भाड़ा मांग रहे हैं। तेजपाल ने अब आलू को बोरियों में भरकर पेड़ के नीचे रखवा दिया है। वह कहते हैं, 'कोल्ड स्टोरेज पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे आलू नहीं रख रहे हैं।' ट्रक ड्राइवर मौसम कोलकाता से 16 टन हरी मिर्च लेकर तड़के तीन बजे आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे। इस यात्रा में उन्हें 29 घंटे लगे और वह इनाम पाने से महज एक घंटे पीछे रह गए। अगर वह 28 घंटे में पहुंच जाते, तो उन्हें अपने मालिक से 8,000 रुपये का इनाम मिलता। राजस्थान के मेवात के रहने वाले 22 वर्षीय मौसम ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा कि पुलिसवालों ने रास्ते में उन्हें कम से कम 25 बार रोका। उन्होंने कहा, 'हर बार रोके जाने पर मुझे 200 से 500 रुपये देने पड़े। साथ ही उन्हें रास्ते में खाने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा।' देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। वह कहते हैं, 'पूरे सफर के दौरान मैंने हाइवे पर गरीबों को पैदल जाते देखा। इनमें पुरुषों और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। वह लिफ्ट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन निगरानी के कारण मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था।' मौसम अपने ट्रक के करीब बैठे हैं और उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे मथाडी दिलीप प्रसाद को काम की तलाश है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वह छह बजे से मंडी में बैठे हैं। बिहार के नवादा के रहने वाले प्रसाद ने कहा, 'इस समय तक मैं थोक और खुदरा कारोबारियों के लिए मंडी के गेट तक सब्जी और की बोरियां ढोकर 300 रुपये कमा लेता था। आज मेरी अब तक केवल 30 रुपये की कमाई हुई है।'

बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरस आजकल पूरी दुनिया में कहर ढा रहा है। लेकिन देश के दूसरे थोक बाजारों की तरह आजादपुर मंडी में भी सामाजिक दूरी लोगों की प्राथमिकता में नहीं है। किसान, ट्रकवाले, मजदूर और आढ़ती अपने काम में व्यस्त हैं और इस दौरान एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनमें से कुछ ने अपने मुंह पर कपड़ा लगा रखा है।

यह वजूद बचाने के लिए संघर्ष है और इसमें सरकार उनकी कोई खास मदद नहीं कर रही है। लॉकडाउन के बावजूद किसान खेतों से मंडी तक सब्जियां और फल पहुंचाते हैं और ठेले वाले वहां से इन्हें लादकर गली मोहल्लों में पहुंचाते हैं। जब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, तो ये लोग सब्जी हमारी मेज तक पहुंचाने के लिए पसीना बहाते हैं। अधिकांश मध्य वर्गीय परिवारों ने फल और सब्जी की किल्लत नहीं देखी है, इसलिए उनके लिए ऐसे लोगों के संघर्ष की कल्पना करना मुश्किल है। वे इन लोगों की परेशानियों से वाकिफ नहीं हैं जो इस आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हैं।

इस्लामपुर के किसानों की मुख्य फसल आलू और खीरा है। वे अभी जनवरी के मध्य में हुई बेमौसम बारिश की मार से भी नहीं उबर पाए थे कि लॉकडाउन ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संयोग से लॉकडाउन ऐसे वक्त हुआ है, जब रबी की फसल कटने को तैयार है। एक किसान ने कहा, 'सरकार ने कुछ छूट देने की घोषणा की है, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। अचानक मजदूरों की कमी से फसल कटने में देरी हुई है।'

इस समय पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से गेहूं, चना और सरसों की फसल काटी जाती है। मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता भगवान मीणा ने बुधनी से फोन पर कहा, 'मध्य प्रदेश और राजस्थान में लॉकडाउन से पहले चने और गेहूं की अधिकांश फसल कट चुकी थी। किसानों को फसल रखने के लिए प्लास्टिक शीट और बोरे नहीं मिल रहे हैं। अगर मौसम खराब हुआ तो भगवान ही मालिक है।'

अधिकांश राज्य सरकारों ने खरीद प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों को देर से कटाई की सलाह दी है क्योंकि उत्तरी भारत में मौसम अब भी ठंडा बना हुआ है। किसानों और उपभोक्ताओं पर इसका असर आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा।

देश भर में लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही यह मुंबई में लागू कर दिया गया था। अब मुंबई और ठाणे को सब्जी और फलों की आपूर्ति करने वाली कृषि उपज विपणन समितियां यानी थोक मंडियां कारोबारियों को इस बात के लिए परमिट जारी कर रही हैं कि वे कितनी मात्रा में सब्जियां बिक्री के लिए ला सकती हैं।

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने से सब्जियों की मांग में भारी कमी आई है। कारोबारी पहले किसानों से सब्जियां खरीदकर पास की मंडी में बेचते थे, लेकिन अब उन्हें दूर की मंडियों में जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खरीदार मिलेंगे या नहीं।

कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है जिनमें कारोबारी मंडियों के बाहर फल और सब्जी फेंककर चले गए या किसानों ने अपनी फसल गांवों के बाहर फेंक दी। रामभूल की तरह कुछ किसानों ने अपनी फसल मवेशियों को खिला दी। मुंबई से नासिक जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले इगतपुरी से किसानों ने हाल में लौकी और बंदगोभी आदि की अपनी फसल फेंक दी थी क्योंकि वे उसे बेच नहीं पाए।

कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है जिनमें कारोबारी मंडियों के बाहर फल और सब्जी फेंककर चले गए

नासिक में हर साल 12.5 लाख टन अंगूर होता है जो देश के कुल उत्पादन का 40 फीसदी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण प्रवासी कामगार अपने घरों को जा चुके हैं। अंगूर की खेती और इसका निर्यात करने वाले किरण चुंभले कहते हैं, 'मजदूरों की इतनी कमी है कि हमें अंगूर निकालने में देरी करनी पड़ रही है या ताजे अंगूरों को किशमिश बनानी पड़ रही है। केवल 30 फीसदी मजदूर ही रह गए हैं जिनमें से अधिकांश स्थानीय हैं। वे मोटा पैसा मांग रहे हैं।'

चुंभले खेती की नई तकनीक से वाकिफ हैं जिससे अंगूरों को ताजा बनाए रखनें में मदद मिलती है और वे लंबे समय तक मीठे बने रहते हैं। लेकिन अधिकांश किसान इससे अनभिज्ञ हैं। नासिक की किसान संस्था दाभोलकर प्रयोग परिवार के संयोजक वासुदेव काथे ने कहा कि अधिकांश किसानों के पास किशमिश बनाने की विशेषज्ञता, सामग्री और सॉल्वेंट नहीं है। यह 5,000 किसानों की संस्था है। वे फसल में सुधार के अनुभवों को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण मुंबई से आपूर्ति नहीं हो रही है। काथे ने कहा, 'मैं 35 साल से अंगूर की खेती कर रहा हूं और मैंने अब तक कभी इतना गंभीर संकट नहीं देखा है।' केंद्रीय कृषि विभाग के मुताबिक देश में अंगूर उत्पादन 29 फीसदी की गिरावट के साथ 21.5 लाख टन रहने का अनुमान है।

देश के कुल प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 37.2 फीसदी है जिसमें से कुछ प्याज नासिक में भी उगाया जाता है। लेकिन नासिक से 60 किमी दूर लासलगांव स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी बंद है क्योंकि पास के एक इलाके में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। किसानों को लासलगांव के करीब स्थित चंदवाड़ जैसी छोटी मंडियों में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। इससे प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है क्योंकि फसल तैयार होने के इस मौसम में किसान प्याज नहीं बेच पा रहे हैं।

मुंबई की वाशी मंडी में हर साल लाखों टन अनाज और दलहन की बिक्री होती है। यहां आकर आप यह सबक ले सकते हैं कि किसी महामारी में चीजों को कैसे संभाला जाता है। वाशी कृषि विपणन समिति के निदेशक नीलेश वीरा कहते हैं, 'हमने भीड़भाड़ को काबू करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि मुंबई शहर और ठाणे में किसानों और कारोबारियों की ओर से आपूर्ति चालू रहे। समिति ने एक 16 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है।' मंडी में आने और मुंबई से बाहर जाने वाले ट्रकों में एक दिन माल उतारा जाता है और एक दिन चढ़ाया जाता है। केवल पहचान पत्र रखने वालों को ही मंडी में आने की अनुमति है। व्यक्तिगत खरीदारों, ब्रोकरों और दूसरे लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है। मंडी को प्रवेश और निकास द्वारों पर सख्त पहरा है। कोंकण जिले तक सभी नगर निगमों के आयुक्तों की समिति इसका कामकाज देख रही है। वाशी बाजार की एक स्थानीय समिति इसका आंतरिक कामकाज संभाल रही है।

मंडी में कितनी मात्रा में सब्जी लाई जा सकती है, इसके लिए परमिट जारी किए गए हैं। वाशी मंडी से नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघर और वसई-विरार तक आपूर्ति होती है। यहां भी व्यक्तिगत ग्राहकों का प्रवेश वर्जित है और मंडी में नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है।

हालांकि मुंबई के उपनगरीय इलाकों में खुदरा कारोबारी सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जबकि किसान उन्हें सस्ते में अपनी फसल बेच रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सब्जियो को ढोना महंगा पड़ रहा है। हालांकि घरों में दोगुना खरीदारी हो रही है, लेकिन इससे रेस्टोरेंटों, ढाबों और होटलों के बंद होने से कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है।

उधर आजादपुर मंडी में पहुंचे 48 साल के अर्जुन को दिल्ली में ही रहने के अपने फैसले पर अफसोस है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले अर्जुन मंडी में सब्जी बेचते हैं। उन्होंने अपना मुंह और नाक गमछे से ढका है। अर्जुन ने कहा, 'मैंने सोचा कि मैं कमाई करता रहूंगा क्योंकि मैं जरूरी चीज बेचता हूं। व्यक्तिगत खरीदार मंडी नहीं आ रहे हैं जिससे कमाई बहुत कम रह गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं अपने बच्चों के पास गांव चला जाऊंगा।'

मंडी के भीतर संकरी गलियों में दुकानदार सब्जी बेचते थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। मंडी से सब्जियां खरीदकर थोक और खुदरा कारोबारियों को बेचने वाले 22 साल के मनीष सिंह ने कहा, 'इस बाजार का ढांचा ऐसा है कि यहां सामाजिक दूरी रखना मुश्किल है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ऐसा खतरा है जिससे खेले बिना गुजारा नहीं है।' प्रसाद ने कहा, 'मैं यह काम नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा।'

कृषि उपज की बिक्री के नियमों में ढील

किसानों को अपनी उपज सीधे खुदरा श्रृंखलाओं, थोक खरीदारों को बेचने की मंजूरी

राजेश भयानी

केंद्र सरकार की तरफ से जारी बहुत सी अधिसूचनाओं और हाल ही में राज्यों को लिखे गए पत्रों से उपभोक्ता की मेज पर कृषि एवं खाद्य उत्पाद समय पर और बिना किसी अड़चन के पहुंचेंगे। इन उपायों में एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) के क्षेत्राधिकार को मंडी क्षेत्र तक सीमित करना, बड़े खुदरा विक्रेताओं और जिंस प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे किसानों से खरीद की मंजूरी देना और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की खातिर पास जारी करने के लिए प्राधिकरण को विकेंद्रित बनाना आदि शामिल हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे एपीएमसी अधिनियम और मंडियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में तीन महीने के लिए ढील दें। इसके तहत किसानों को बिना किसी लाइसेंस या पंजीकरण प्रक्रिया के बड़े खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री की मंजूरी दी जाए। हालांकि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को यह मंजूरी देनी होगी।

इस कदम से हजारों दाल मिलें, तिलहन पेराई इकाइयां और आटा मिल इन जिंसों की सीधे खरीद कर पाएंगी। दलहन और खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योगों ने कहा है कि उन्हें सीधे किसानों से खरीद की मंजूरी दी जाए।

राज्यों को केवल तीन महीने के लिए सभी एपीएमसी का दायरा उनके मंडी क्षेत्र तक सीमित करने को कहा गया है। वेयरहाउस डेवलपमेंट ऐंड रेग्यूलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत सभी गोदामों को मार्केट यार्ड के रूप में अधिसूचित किया है। इससे किसानों को अपने दरवाजे पर जिंसों को बेचने में मदद मिलेगी। सभी प्रसंस्करणकर्ता, थोक खरीदार मंडी गए बिना किसानों से जिंसों की खरीद कर पाएंगे।

इसके अलावा गृह सचिव की तरफ से भी प्रशासकों और कृषि मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्रों में कहा गया है कि मंजूरी की प्रक्रिया को विकेंद्रित बनाया जाए। इनके अलावा केंद्र सरकार पहले ही ई-राष्ट्रीय कृषि विपणन प्लेटफॉर्म (ई-नाम) पर कारोबार के नियम नरम बना चुकी है। यह प्लेटफॉर्म 16 राज्यों में 585 मंडियों से जुड़ा है।

इन विभिन्न पत्रों में लोगों द्वारा रोजाना उपभोग किए जाने वाले खाद्य एवं किराने के उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्यों एवं प्रशासकों को आवश्यक वस्तुओं की इस परिभाषा का पालन करने के लिए कहा गया है।

जिले के अधिकारी उन गतिविधियों और सेवाओं के लिए पास जारी कर रहे हैं, जो आवश्यक और छूट की श्रेणी के तहत आती हैं। हालांकि जिन उद्यमों की देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने कहा, 'सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे उन कंपनियों या संगठनों को स्वीकृति पत्र जारी करें, जिनकी देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला है। राज्य सरकारें इन कंपनियों को अहम कर्मचारियों और कामगारों की सुगम आवाजाही के लिए रीजनल पास जारी करने की मंजूरी दें ताकि उनकी राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला चालू रहे। ऐसी मंजूरियां कम से कम रखी जाएं।' राज्य प्रशासकों और मुख्य सचिवों से कहा गया है कि रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों के मनोनीत अधिकारियों को उन कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को पास जारी करने की मंजूरी दी जाए, जो ऐसी सेवाओं के लिए आवश्यक हैं।

पत्र में कहा गया कि राज्यों के भीतर आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले ट्रकों के लिए ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को यात्रा की मंजूरी दी जा सकती है और खाली ट्रक बिल, ई-वे बिल आदि अपने पास रख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों को उपज मंडियों में लाए बिना ई-नाम पर बेचने की मंजूरी दी गई थी। नियमित ई-नाम गोदामों द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिट कारोबार को आसान बनाएंगी। कारोबारी, प्रसंस्करणकर्ता ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जिंस खरीद सकते हैं और अपने फैसले को आसान बनाने के लिए यह पता लगा सकते हैं कि किस गोदाम में जिंस उपलब्ध हैं।

एनसीडीईएक्स में ईवीपी (कारोबार) कपिल देव ने कहा, 'किसान इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसिट के जरिये अपने कीमत जोखिम की हेजिंग के लिए वायदा प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।'

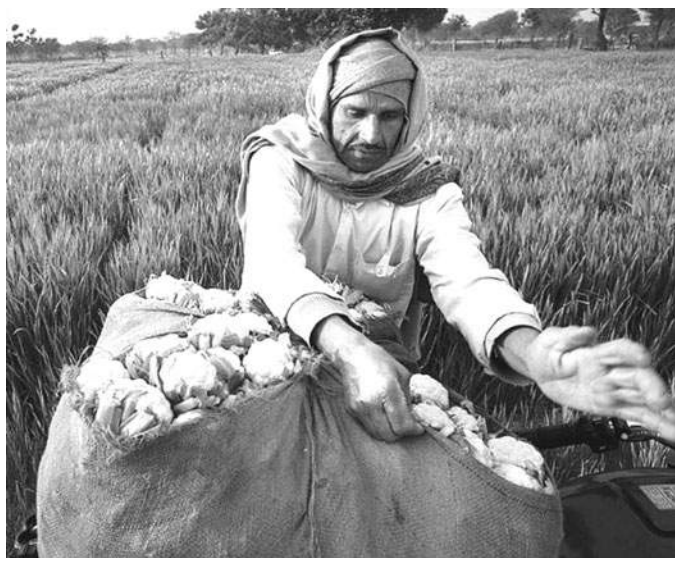

लॉकडाउन के बाद केंद्र की सलाह

- सरकार ने राज्यों से कहा कि एपीएमसी का दायरा मंडी क्षेत्र तक सीमित किया जाए
- वेयरहाउस डेवलपमेंट ऐंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत सभी गोदामों को बाजार यार्ड के रूप में अधिसूचित किया
- बड़े खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और थोक खरीदारों को किसानों से सीधे खरीदने की मंजूरी दी जाए
- राष्ट्रीय श्रृंखलाओं वाली कंपनियों को क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए पास जारी करने का अधिकार
- रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को आवश्यक लोगों को पास जारी करने की मंजूरी मिले
- ट्रक में चालक और एक अन्य व्यक्ति को यात्रा को मंजूरी मिले
- खाली ट्रक लौटते समय इनवॉयस या ई-वे बिल अपने पास रखें

मार्केट यार्ड घोषित होंगे गोदाम

राजेश भयानी

देश के किसान अब जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) पोर्टल पर सीधे अपने उत्पाद बेचने में सक्षम हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वे शर्तें पूरी करने के लिए कहा है, जिनके तहत ई-नाम से जुड़ते वक्त उन्होंने अपने गोदामों को मार्केट यार्ड (कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री एवं मूल्यांकन केंद्र) घोषित करने पर हामी भरी थी।

देश में लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए कई अन्य उपायों पर भी काम चल रहा है। इनमें फसलों को किसान संगठनों के संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से ई-नाम पर इनकी बिक्री के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके साथ ही परिवहन सेवा प्रदाताओं को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। ये सभी सुधार अप्रैल तक लागू करने की योजना तैयार की गई है। इस वर्ष अप्रैल में ई-नाम व्यवस्था को अस्तित्व में आए चार वर्ष पूरे हो जाएंगे।

राज्य की कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीपीएमसी) जब इन ई-नाम व्यवस्था से जुड़ती हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। हालांकि इसके लिए राज्यों को तीन शर्तें पूरी करनी पडती हैं। सबसे पहले उन्हें वेयरहाउस विकास नियामक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत गोदामों को मार्केट यार्ड घोषित करना पड़ता है। अन्य शर्तों में केंद्र के प्रस्तावित एपीएमसी कानून को लागू करना भी शामिल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपने गोदामों को मार्केट यार्ड-मंडी घोषित कर दिए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे क्रमश: 14 और 23 गोदाम हैं। कोविड-19 संकट के बीच किसानों की परेशानियां दूर करने के लिए ये सभी कदम उठाए गए हैं। किसान अब तक अपने उत्पाद मंडियों तक लाते रहे थे, लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार के बाद मंडियां या तो बंद हैं या फसल के परिवहन के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं।

- किसान मंडी में लाए बिना उत्पादों की कर सकेंगे बिक्री
- किसान उत्पाद संगठनों को सरकार से मिलीं कई रियायतें

दलहन, तिलहन पेराई इकाइयां और फ्लोर मिलों तक लॉकडाउन के कारण जिंस नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन दिक्कतों के बीच सरकार ने ई-नाम व्यवस्था से जुड़े राज्यों को डब्ल्यूडीआरए के तहत पंजीकृत गोदामों को बाजार के तौर पर अधिसूचित करने के लिए कहा है। देश के करीब 16 राज्य इस बात के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने अब तक अपने किसी गोदाम को मार्केट यार्ड घोषित नहीं किया है। सरकार में एक सूत्र ने बताया कि राज्यों को इस बारे में औपचारिक तौर पर सूचित किया जाएगा। सरकार ने ई-नाम पोर्टल से देश के 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मंडियों को जोड़ दिया है। इनके अलावा देश की 416 और मंडियां भी ई-नाम पोर्टल से जोड़ी जाएंगी, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 1,000 हो जाएंगी।

ई-नाम व्यवस्था के किसान अपनी फसलें गोदामों तक ला सकते हैं। गोदामों में उनकी फसलों का वर्गीकरण गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा और अगर गोदाम मार्केट यार्ड घोषित किए गए हैं तो वे एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जारी करेंगे। यह रिसीट ई-नाम से जोड़ दी जाएगी। इस तरह, यह रिसीट फ्रीली ट्रांसफरेबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ईएनडब्ल्यूआर मानी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद किसानों पर उनकी बिकी फसलों की आपूर्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी और खरीदारों को ही इसका प्रबंध करना होगा। रिपॉजिटरी ऐसी रिसीट और उनके हस्तांतरण का लेखा-जोखा उसी तरह रखेंगे जैसा डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों के मामले में करते हैं। एनसीडीईक्स और अन्य निवेशकों द्वारा स्थापित रिपॉजिटरी एनईआरएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी केदार देशपांडेय ने कहा, 'ईएनडब्ल्यूआर-ई-नाम संयुक्त व्यवस्था से गोदाम के स्तर पर बिक्री बढ़ेगी और किसानों के समक्ष मजबूरी में सस्ते दाम पर अपने उत्पाद बेचने की नौबत नहीं आएगी। इससे अनाज एवं अन्य फसलों के परिवहन पर आने वाला खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।'

सरकार ने एक अन्य अहम सुधार की भी घोषणा की है, जिससे किसानों को मंडी आने की जरूरत नहीं होगी। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अपने उत्पाद एपीएमसी में लाए बिना संग्रह केंद्रों पर बेच सकते हैं। दूर बैठे खरीदारों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए किसान अपने उत्पाद एवं इसकी गुणवत्ता के प्रमाण की फोटो अपने परिसरों से अपलोड कर सकते हैं। एफपीओ को उनके परिसरों से उत्पाद की आपूर्ति का अधिकार है या फिर वे सफल बोली के बाद इसे मंडी तक भी ला सकते हैं। देश में हजारों एफपीओ हैं। सरकार इनके संग्रह केंद्रों को गोदामों के तौर पर पंजीकृत कर रही है, जिन्हें बाद में ई-नाम से जोड़ा जा सकता है।

नई दिल्ली | 7 अप्रैल 2020 मंगलवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

'धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाया जाए'

कोविड-19 के बेहद कम असर वाले क्षेत्रों में विभाग फिर चालू करने की होगी तैयारी

एजेंसियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को उन इलाकों में धीरे-धीरे विभिन्न विभाग खोलने की योजना तैयार करने के लिए कहा है, जहां कोरोनावायरस के मामले कम हैं।

प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही यह संकेत भी दिया कि देश में लॉकडाउन धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले असर को कम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा।

देश में इस समय 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है और केवल आवश्यक सेवाओं जारी रखने की ही इजाजत दी गई है। कोरोनावयरस से भारत सहित पूरी दुनिया में खलबली मची है और इसने 70,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। इस महामारी से दुनिया भर में करीब 183 देशों के 12.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की। मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि उन इलाकों में विभिन्न विभाग सतर्कता के साथ धीरे-धीरे खोले जाने चाहिए जहां कोरोनावायरस का प्रकोप कम है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश में एक साथ लॉकडाउन खत्म करना मौजूदा हालात में संभव नहीं

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की

- कोरोना से दुनिया भर में करीब 183 देशों के 12.8 लाख लोग प्रभावित हुए
- मोदी ने अपने मंत्रियों से कोरोना से आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले असर को कम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करने को कहा
- मोदी ने मंत्रियों से कारोबार निरंतर जारी रखने से जुड़ी योजना तैयार करने के लिए कहा
- मोदी ने फसल कटाई के समय में किसानों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या विभिन्न क्षेत्रों का परिचालन एक साथ शुरू नहीं कर धीरे-धीरे उन्हें इसकी अनुमति देनी चाहिए । उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि लॉकडाउन के उपाय और सामाजिक संपर्क कम करने के उपाय दोनों साथ-साथ जारी रहना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों से हाल में ही शुरू किए गए आरोग्य सेतु ऐप्लीकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के सभी उपाय करने के लिए कहा।

प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर वायरस का असर कम से कम करने के लिए मुस्तैदी से काम होना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों से कारोबार निरंतर जारी रखने से जुड़ी योजना तैयार करने के लिए कहा। लॉकडाउन का असर खत्म करने के लिए सरकार ने गरीब लोगों एवं मजदूरों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने आय कर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों और फसलों की कटाई पर कोविड-19 के असर और इनसे निपटने के उपाय करने पर भी चर्चा की। मोदी ने मंत्रियों से ऐप आधारित कैब सेवाओं की तर्ज पर ही ट्रक सेवा शुरू करने की संभावना तलाश करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी।

मोदी ने कहा-किसानों का कल्याण हमारे लिए अहम है। सरकार फसल कटाई के समय में किसानों को हरसंभव मदद देगी। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने का सुझाव दिया।

सरकार को हालात काबू करने का भरोसा

सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं

रुचिका चित्रवंशी

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती तादाद के बीच इस्लामी संप्रदाय की तबलीगी जमात से जुड़े करीब 25,500 से अधिक लोगों को संक्रमित होने की आशंका में अलग रखा गया है। सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि हरियाणा के पांच गांवों की पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। देश में कोरोनावायरस के 4,000 से अधिक मामले की पुष्टि अब तक हो चुकी है।

रविवार से लेकर सोमवार तक संक्रमण के कुल 693 नए मामले की पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 4,067 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 1,455 संक्रमितों का ताल्लुक तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं और उनके संपर्क में आने वाले लोगों से है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोविड-19 संक्रमण से 109 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 63 फीसदी मौत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की हुई है, जबकि संक्रमित लोगों में से केवल 19 फीसदी ही उस आयु वर्ग के थे। मरने वाले 86 फीसदी से अधिक लोगों को संक्रमण के अलावा मधुमेह, गुर्दे या दिल से जुड़ी अन्य बीमारी भी थी। इससे यह भी अंदाजा लगा कि उन युवाओं के लिए भी यह संक्रमण खतरनाक होगा जिनमें इस तरह की कोई बीमारी होगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 37 फीसदी मौत 60 साल से कम उम्र के लोगों की हुई है। वहीं 40 साल से कम उम्र के लोगों में से केवल सात फीसदी मौत हुई। हालांकि इस उम्र वर्ग के लोगों में संक्रमण की अधिकतम तादाद देखी गई जो करीब 47 फीसदी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 'अगर हम संक्रमण की शृंखला को तोड़ना चाहते हैं तो हमें लोगों से मिलना-जुलना बंद करने के साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। जिन युवाओं को पहले से ही कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है, उनके लिए भी खतरा है और उन्हें अपने परिवार में बुजुर्गों के भी संक्रमित न होने के लिए सावधान रहना चाहिए।'

पुरुषों में कोरोना संक्रमण ज्यादा

संक्रमित लोगों में महिला-पुरुष के आधार पर जायजा लेने से अंदाजा मिलता है कि काफी हद तक पुरुष ही संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 के 76 फीसदी मरीज पुरुष, जबकि 24 फीसदी महिलाएं हैं। कोरोनावायरस की वजह से मरने वालों में भी करीब 73 फीसदी पुरुष थे। वैश्विक स्तर पर भी कोरोनावायरस का प्रभाव महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर ज्यादा देखा गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के एक संगठन ग्लोबल हेल्थ 50/50 द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जर्मनी सहित 14 देशों में कोरोनावायरस से हुई 50 फीसदी मौत पुरुषों की हुई।

संक्रमित मरीजों में 76 फीसदी पुरुष जबकि 24 फीसदी महिलाएं हैं

मिसाल के तौर पर दक्षिण कोरिया में संक्रमण के 40 फीसदी मामलों की पुष्टि पुरुषों में की गई जबकि संक्रमण से हुई 53 फीसदी मौत भी पुरुषों की हुई। वहीं, आयरलैंड में अब तक 48 फीसदी पुष्ट मामलों से पुरुष ही जुड़े थे, जबकि 69 फीसदी मौत भी पुरुषों की हुई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि धूम्रपान, तंबाक और शराब पीने की दर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में काफी अधिक है। ग्लोबल हेल्थ 50/50 की रिपोर्ट में कहा गया, 'ऐसी आदतों से दूसरी बीमारियों के होने का खतरा तो होता ही है और इसकी वजह से कोविड-19 का भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है।' इटली और डेनमार्क में कोविड-19 की वजह से हुई करीब 71 फीसदी मौत पुरुषों में देखी गई। भारत में महिलाओं में संक्रमण कम होने की वजह यह भी हो सकती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेती हैं या उनकी बातचीत भी कम होती है।

नियंत्रण के उपाय

अग्रवाल ने बताया कि राज्यों को संक्रमण के संदिग्धों की निगरानी करने, उन्हें अलग रखने की सुविधाएं देने, चिकित्सा उपकरणों की खरीद आदि के लिए सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर सरकार ने कहा कि इस दवा से राहत मिलने के प्रमाण बेहद सीमित हैं ऐसे में इस दवा के इस्तेमाल की सिफारिश करना भी मुश्किल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में महामारी विज्ञान और संचारी रोग प्रमुख रमन गंगाखेडकर कहते हैं, 'इलाज के लिए इस दवा के इस्तेमाल का हमारे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। केवल 30 मरीजों का ही अध्ययन किया गया है।'

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजने की गुजारिश की थी जिसकी आपूर्ति कम हो रही है ताकि कोविड-19 महामारी का सामना करने में मदद मिल सके। 25 मार्च को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर मलेरिया और त्वचा पर सूजन जैसी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है।

सरकार ने कहा कि भारत इस समय चरण-2 से चरण-3 के बीच है और फिलहाल यह सामुदायिक प्रसार के स्तर तक नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय को आशंका है कि संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसे भरोसा है कि सक्रिय कार्रवाई के जरिये इसे संभाला जाएगा। भीलवाड़ा में जिस तरह रोकथाम की रणनीति अपनाई जा रही है उसका पालन सभी राज्य कर रहे हैं।

दुनिया की नजरों में पहले भी खटक चुका है तबलीगी

फोटो: दलीप कुमार

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कुछ लोग संक्रमित मिले थे

आदिति फडणीस

विकीलीक्स ने गुआंतानेमो बे जेल में बंद अल-कायदा आतंकवादियों से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए यह खुलासा किया था कि अल-कायदा ने यात्रा के कागजात तैयार करने और पनाह लेने के लिए नई दिल्ली स्थित संगठन तबलीगी जमात का इस्तेमाल एक छद्म के तौर पर किया था। लीक हुए कागजात के मुताबिक उस जेल में बंद कम-से-कम तीन लोग तबलीगी के दिल्ली और आसपास के ठिकानों में रह चुके थे।

तबलीगी जमात इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी की इमारत में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम के बाद देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने के बाद इसका नाम चर्चा में है। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में भी ऐसे समारोहों के बाद वहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए थे।

विकीलीक्स ने उन दस्तावेजों की जानकारी दी थी जिनमें इस अमेरिकी जेल में बंद 779 कैदियों से हुई पूछताछ का ब्योरा और उनका विश्लेषण मौजूद था। अमेरिकी रिकॉर्ड में इसका नाम जमात तबलीग यानी जेटी के रूप में दर्ज है। इसके मुताबिक जेटी एक धर्मांतरण-केंद्रित संगठन है जो अपनी इच्छा से आतंकियों का सहयोग करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अल-कायदा ने जमात तबलीग का इस्तेमाल अपने सदस्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के इंतजाम और धन जुटाने में किया।

तबलीगी जमात के पदाधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि उनके प्रतिष्ठान सभी के लिए खुले हुए हैं। विकीलीक्स खुलासों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हुए जमात ने कहा था, 'हर कोई जानता है कि इस तरह के बयान दबाव डालकर दिलवाए जाते हैं।' हम इतना जरूरत जानते हैं कि यह कब शुरू हुआ था। पहले तबलीगी जमात न तो इस्लामी कट्टरता के समर्थन में लिप्त था और न ही इसको बढ़ावा देता था। असल में यह एक सुधारवादी संगठन था। विद्वान इसे एक अराजनीतिक भक्ति आंदोलन के तौर पर देखते हैं जो व्यक्तिगत आस्था, आत्म-परीक्षण और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता था। लेकिन इस सफर के दौरान ही यह संगठन अपने मौलिक उद्देश्य से भटक गया।

हम जानते हैं कि तबलीगी जमात की शुरुआत प्रमुख देवबंदी धर्मगुरु एवं विद्वान मौलाना मुहम्मद इलियास कंधालवी (1885-1944) ने वर्ष 1927 में दिल्ली से कुछ दूर मेवात में की थी। तबलीगी जमात के गठन के पीछे का एक कारण हिंदू प्रचारकों की पहल से मुकाबला करना भी था। इसके अनुयायियों ने आधुनिकता को इस्लाम का प्रतिपक्षी बताते हुए खारिज कर दिया, इसके दायरे से महिलाओं को बाहर रखा और यह उपदेश दिया कि इस्लाम में अन्य धर्मों को मिला देना चाहिए। जमात के अनुयायियों को कुरान के अलावा सिर्फ 'तब्लीगी निसाब' ही पढ़ने की इजाजत है। सात निबंधों के इस संग्रह को इलियास के एक साथी ने 1920 के दशक में लिखा था।

> अलेक्सीव का दावा है कि फ्रांस में सक्रिय करीब 80 फीसदी इस्लामी कट्टरपंथी तबलीगी जमात से ही आते हैं

तबलीगी जमात के बारे में इस तथ्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यह एकाश्म सोच नहीं रखता है। जमात के मशहूर जानकार अलेक्जेंडर आर अलेक्सीव के मुताबिक, इसका एक धड़ा यह मानता है कि उसे 'जमीर के दम पर जिहाद' (जिहाद बिन नफ्स) करना चाहिए जबकि कट्टरपंथी धड़ा 'तलवार के दम पर जिहाद' (जिहाद बिन सैफ) की वकालत करता है। सुन्नी संप्रदाय के लोकप्रिय वहाबी-सलाफी मत से सतही तौर पर अलग न होने के बावजूद तब्लीगी जमात को इस्लामी दुनिया में तवज्जो मिलने की वजह इसके कठोर नियम, धर्मांतरण पर जोर और सेवा की भावना ही लगती है। सऊदी अरब इस आंदोलन को एक खतरे के तौर पर देख सकता था लेकिन उसने इसे लेकर सहयोगी रवैया दिखाया, फंड दिया और इसकी भावना की तारीफ करने के साथ दूसरों को इसका पालन करने की सलाह भी दी।

जमात को आगे बढ़ाने में असली भूमिका पाकिस्तान के हुक्मरानों की रही है। खासकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पिता तब्लीगी जमात के बड़े पैरोकार हुआ करते थे। पाकिस्तान के रायविंड में स्थित तब्लीगी का केंद्र रंगरुटों के लिए अपना मिशनरी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सैन्य प्रशिक्षण का एक जाना-माना भर्ती स्थान है। अलेक्सीव के साक्षात्कार एवं जमात के बारे में किए शोध से पता चलता है कि तबलीगी जमात ने हरकत-उल-मुजाहिदीन के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। रायविंड में 1980 में स्थापित हरकत-उल-मुजाहिदीन के लगभग सारे ही शुरूआती सदस्य तबलीगी मत से जुड़े हुए थे। दिसंबर 1998 में एयर इंडिया के एक यात्री विमान को अगवा करने और कराची में फ्रांसीसी इंजीनियरों को ले जा रही बस पर फिदायीन हमले के लिए बदनाम हो चुके हरकत के सदस्य तब्लीगी के साथ अपने रिश्तों को छिपाने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। अलेक्सीव ने हरकत के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को यह कहते हुए उद्धृत किया था, 'दोनों ही संगठन एक साथ मिलकर सच्चे जिहादी मुस्लिमों का एक असली अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करते हैं।'

अलेक्सीव की मानें तो तब्लीगी जमात का ही एक अप्रत्याशित परिणाम हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी रहा है। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के बाद गठित यह संगठन न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि गुजरात में भी सक्रिय रहा है। गुजरात में तो कट्टरपंथियों के इस समूह ने करीब 80 फीसदी मस्जिदों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है जिनकी कमान पहले उदारवादी बरेलवी मत के अनुयायियों के पास हुआ करती थी। अलेक्सीव का दावा है कि फ्रांस में सक्रिय करीब 80 फीसदी इस्लामी कट्टरपंथी तबलीगी जमात से ही आते हैं। यही कारण है कि फ्रांसीसी खुफिया अधिकारियों ने तबलीगी जमात को 'रूढ़िवादिता की ड्योढ़ी' करार दिया है। अमेरिका के आतंक-रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारी भी इस राय से सहमत नजर आते हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद प्रकोष्ठ के उप-प्रमुख ने 2003 में कहा था, 'अमेरिका में तबलीगी जमात की अच्छी-खासी मौजूदगी हो चुकी है।'

भारत में लोकप्रिय हो रहे जूम पर खतरा

पृष्ठ 1 का शेष

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमने इस बारे में जूम से बात की है और कंपनी से आश्वासन दिया है कि भारत के डेटा को चीन के सर्वरों में नहीं भेजा जा रहा है।' इसी तरह बैठकों में जूम का व्यापक इस्तेमाल करने वाली कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि उन्हें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर जूम के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे रही है।हालांकि साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा संवेदनशील बैठकों के लिए यूजरों को अधिक सुरक्षित ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी फर्म एवलांस ग्लोबल सॉल्यूशंस के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी मनन शाह ने कहा, 'मैं निजता सुनिश्चित करने के लिए एंड टु एंड इनक्रिप्टेड वीडियो प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की सलाह दूंगा।'

मुंबई में 26 नर्स, 3 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित

बीएस संवाददाता

देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। लोगों की जान बचाने वाले अस्पताल भी अब कोरोना की चपेट में आने लगे हैं जिससे स्थिति और भी भयानक हो गई है। दक्षिण मुंबई के बड़े अस्पताल वॉकहार्ट के डॉक्टर और नर्सों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एक हफ्ते में 26 नर्सों और तीन डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को बीएमसी ने सील कर दिया है। अब यहां पर महत्त्वपूर्ण टीमों के अलावा कोई नहीं जा सकेगा। वॉकहार्ट के अलावा राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी कोरोना ने डॉक्टरों और नर्सों को अपनी गिरफ्त में लिया है।

महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद भी वॉकहार्ट अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन चिंता में पड़ गया है। महाराष्ट्र में सोमवार सुबह 33 नए मरीज सामने आए है। इसी के साथ संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर

तकरीबन 800 हो गया है। इनमें से 19 मामले पुणे, 11 मुंबई, एक-एक मामला सातारा, अहमदनगर और वसई से सामने आए हैं। मुंबई से सटे वसई-विरार के नालासोपारा इलाके में एक 65 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। सबसे ज्यादा 113 मरीज रविवार को सामने आए थे। रविवार को ही यहां सबसे ज्यादा 13 मरीजों की मौत हुई है जिसमें नौ मुंबई एमएमआरडीए से, तीन पुणे और एक औरंगाबाद से थे। मुंबई से सटे मीरा भायंदर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17 पहुंच गई। मीरा रोड इलाके में भी वॉकहार्ट अस्पताल है।

बीएमसी ने वॉकहार्ट अस्पताल को एक निषेध क्षेत्र (क्वारंटीन जोन) घोषित कर दिया है। मुंबई सेंट्रल में स्थित इस अस्पताल में किसी नए मरीज की भर्ती पर रोक रहेगी। आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अस्पताल में कैसे इतने ज्यादा लोगों में संक्रमण फैल गया। सभी को सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है। हॉस्पिटल में काम करने वाले 270 से ज्यादा कर्मचारियों और डॉक्टरों की जांच कराई जा रही है। मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल को भी खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जसलोक अस्पताल की छह नर्सों समेत 19 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद इन अस्पतालों में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। 27 मार्च को वॉकहार्ट अस्पताल में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग भर्ती हुए थे। उनकी एंजियोप्लास्टी होनी था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई है। उनके संपर्क में आने वाला स्टाफ भी पॉजिटिव मिला।

हाल में ही वॉकहार्ट में काम कर रहे धारावी में रहने वाले एक सर्जन में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद अस्पताल के सभी स्टाफ का चैकअप किया गया और 26 नर्स और 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले।

औरंगाबाद के जिला अस्पताल में कार्यरत 38 वर्षीय पुरुष नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ की कोरोना जांच करवाई गई है। आज शाम तक इनकी भी रिपोर्ट आने की संभावना है। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आम जनता से अपील की है कि जिस गली, गांव, बस्ती, सोसायटी में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, वहां लोग न जाएं ताकि कोरोना के वायरस से खुद को और अपने परिवार को संक्रमित होने से बचाया जा सके।